ब्यूरो दर्पण

ब्यूरो का 51 वां स्थापना दिवस समारोह

04 सितंबर, 2021 नई दिल्ली

माननीय श्री अमित शाह जी

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार

का संबोधन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

मुख्य अतिथि द्वारा टोक्यो ओलंपिक-2020 की रजत पदक विजेता
सुश्री साईखोम मीराबाई चानू, अपर पुलिस अधीक्षक, मणिपुर पुलिस का सम्मान

ब्यूरो के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव द्वारा
मुख्य अतिथि माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत

ब्यूरो का 51वां स्थापना दिवस समारोह

04 सितंबर, 2021

नई दिल्ली

माननीय श्री अमित शाह जी

केंद्रीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार

का संबोधन

कृपया YouTube पर सुनने हेतु स्कैन करें

उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	समारोह	पृष्ठ सं.
1.	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस समारोह पर दिनांक 04 सितंबर, 2021 को माननीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन	1
2.	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा दिनांक 28 - 29 नवंबर, 2019 को आयोजित 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, के समापन समारोह में माननीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह जी का संबोधन	13
3.	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 49वें स्थापना दिवस पर दिनांक 28 अगस्त, 2019 को माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन	31
4.	Address by the Hon'ble Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah on the occasion of 51st Foundation Day of Bureau of Police Research & Development on 04 September, 2021	43
5.	Address by the Hon'ble Home Minister, Shri Amit Shah in the valedictory function of 47th All India Police Science Congress, organised by Bureau of Police Research & Development at Lucknow on 28 - 29 November, 2019	57
6.	Address by the Hon'ble Home Minister, Shri Amit Shah on the 49th Foundation Day of Bureau of Police Research & Development on 28 August, 2019	75

बालाजी श्रीवास्तव, भा.पु.से.
महानिदेशक

Balaji Srivastava, IPS
Director General

Tel. : 91-11-26781312 (O)
Fax : 91-11-26781315
Email : dg@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

Bureau of Police Research & Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-8, Mahipalpur,
New Delhi-110037

भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, माननीय श्री अमित शाह जी ने दिनांक 04 सितंबर, 2021 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएण्डडी) के 51वें स्थापना दिवस समारोह को अपनी उपस्थिति से अलंकृत किया। इस अवसर पर अपने भाषण में माननीय मंत्री ने ब्यूरो की उपलब्धियों का उल्लेख किया और आने वाले वर्षों में इसकी सफलता की कामना की।

बीपीआरएण्डडी के अधिदेश के विस्तार की आवश्यकता पर बोलते हुए माननीय मंत्री ने सीएपीएफ, आंतरिक सुरक्षा की उभरती चुनौतियों, भूमि और समुद्री सीमाओं से जुड़े प्रश्न, पुलिस की छवि के संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध श्रेष्ठ पुलिस प्रथाओं के अध्ययन तथा सिफारिशों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी को ब्यूरो के चार्टर में शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

माननीय मंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण, अनुसंधान, आधुनिकीकरण और नए विचारों के विकास सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के संबंधों की कड़ी को मज़बूत करने के लिए ब्यूरो की प्रशंसा की। उन्होंने पेशेवर पुलिसिंग के मामलों में कुशल मध्यस्थ के रुप में इसकी भूमिका को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया।

ब्यूरो ने 28-29 नवंबर, 2019 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस (AIPSC) और 28 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में बीपीआरएण्डडी के 49वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया था। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इन दोनों अवसरों पर मुख्य अतिथि के रुप में देश के सभी पुलिस बलों को संबोधित किया। उनके निर्देश पुलिस बलों के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन है। इन तीन अवसरों पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के संबोधन इस "ब्यूरो दर्पण" में प्रकाशित हैं।

(बालाजी श्रीवास्तव)
महानिदेशक

सत्यमेव जयते

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस समारोह पर दिनांक 04 सितंबर, 2021 को माननीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन

आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी श्रीमान नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, डीआईबी श्री अरविंद कुमार जी, DG, BPR&D, श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, SS (IS), श्री वी.एस.के. कौमुदी जी, जिन्होंने एक लम्बे समय तक BPR&D की कमान संभालकर इसकी गति को बरकरार रखा, Addl. DG, BPR&D, श्री नीरज सिन्हा जी, आज यहाँ वर्चुअल तरीके से और फ़िज़िकल तरीके से उपस्थित, सभी प्यारे भाईयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार।

आज BPR&D के 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले तो ढेर से पदक हमारे बहुत सारे पुलिस परिवार के अलग-अलग श्रेणी के अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिले हैं और कुछ संस्थानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए ट्रॉफी मिली है, और विशेषकर सुश्री मीराबाई हमारे बीच में उपस्थित हैं, देश का नाम रोशन कर वो पुलिस परिवार की सदस्य भी बनी हैं, वो भी उपस्थित हैं, उन सभी को मैं हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और उनका जो सातत्य है, श्रम है, और निष्ठा है, उसकी प्रशंसा करता हूँ, उसके लिए उनको साधुवाद भी देता हूँ।

मित्रों आज BPR&D का 51वां स्थापना दिवस समारोह है। कोई भी संस्था जो अपने क्षेत्र में, 51 साल तक अपनी प्रासंगिकता बना सकती है, बनाए रखती है तो उसका मतलब है, उसके काम की प्रासंगिकता भी है, और उसके काम में दम भी है। BPR&D ने दोनों बातों को सिद्ध किया है। मैं, अपने जीवन में लगभग 80 से ज्यादा institutions से जुड़ा हूँ। छोटे से छोटे खादी का काम करने वाली बहनों की संस्था से लेकर, बड़े से

बड़े institution तक, किसी भी संस्थान द्वारा अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि समय निरंतर बदलता रहता है और समय के अनुरूप संस्थाओं को भी बदलना पड़ता है। जो संस्थान इस दृष्टि से अपने-आप को बदलता है, सातत्यपूर्ण performance करता है और परिश्रम करता है, वो ही काल की इस प्रथा में विजयी बनता है। BPR&D के 51 वर्ष के इस काल खंड के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा । मगर मैं समझता हूँ कि BPR&D का काम, बहुत महत्वपूर्ण है । इसीलिए जब मैं पहली बार BPR&D में आया था, तब मैंने विजिटर्स बुक में लिखा था कि **"BPR&D के बगैर अच्छे पुलिसिंग की कल्पना नहीं हो सकती"**।

मित्रों BPR&D एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हमारे संघीय ढांचे में, हमने संघीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है, जिसमें केंद्र सरकार होती है, कई राज्य सरकारें होती हैं, UTs होते हैं और इनके काम के विभाजन के अन्दर, लॉ एंड ऑर्डर, राज्य का विषय है । जब लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय बनता है और संघीय ढांचे को मजबूती देनी होती है, तब सभी राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर की इम्पलीमेंटिंग एजेंसी, मतलब कि पुलिस और उसकी संबंधित संगठनों को जोड़ने वाली एक कड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो चुनौतियाँ होती हैं, वो देश के परिप्रेक्ष्य में आती हैं, सरकारें अलग-अलग पार्टी की, अलग-अलग विचारधारा की, अलग-अलग सोच की होती हैं। कई बार क्षेत्रीय दलों की भी होती हैं। केंद्र में सरकारें कई बार मिली-जुली आती हैं, कई बार एक दल की आती हैं।

इस सबसे हटकर अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपनी चुनौतियों के लिए सक्षम बनना है तो उसके लिए उसको जोड़ने वाली एक कड़ी चाहिए। यदि इस कड़ी की उपलब्धता नहीं है तो देश का लॉ एंड ऑर्डर बिखर जाएगा। मैं मानता हूँ कि 51 साल में BPR&D ने, देश में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, सभी राज्यों को जोड़ने वाली कड़ी का काम बहुत बखूबी किया है, और अच्छे तरीके से किया है। वरना यह असम्भव था कि देश के सामने जो कानून और व्यवस्था की चुनौतियाँ मिली, अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग कानून, कुछ केन्द्रीय कानून, कोई सीमावर्ती राज्य है, कोई मध्य में राज्य है, कोई सागर किनारे से छूता हुआ राज्य

है। इन सारे chanllenges का सामना करना हर एक राज्य के लिए संभव नहीं है। जब तक कोई केंद्रीय व्यवस्था इन सभी चुनौतियों का आकलन करते हुए, इसके वैश्विक मापदंडों का अभ्यास करते हुए, भारत के पुलिस बल को अपग्रेड करने के लिए, हर निस-दिन काम न करे, यह संभव नहीं है। मैं मानता हूँ कि 50 साल तक यह काम BPR&D ने किया है। सभी भूतपूर्व डायरेक्टर भी यहाँ बैठे हैं, मैं सभी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ।

मित्रों हमने आजादी के बाद गणतंत्र को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव है। यदि कोई कहेगा कि यह 15 अगस्त, सन् 1947 को या 1950 में संविधान की स्वीकृति के बाद लोकतंत्र आया है तो यह सही नहीं है। लोकतंत्र हमारे मन का एक स्वभाव है। पहले भी गांव में पंच-परमेश्वर होते थे। हजारों साल पहले द्वारिका में यादवों का गणराज्य चलता था। बिहार के अन्दर कई सारे गणराज्य थे और लोकतंत्र था, यह हमारे देश का स्वभाव है। मगर एक तरह से सोचें तो हमने लोकतंत्र को आजादी के बाद अपनाया है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल आता है तो वह सीधा कानून और व्यवस्था के साथ जुड़ता है। लोकतंत्र का मतलब पार्टियों को वोट देना और पार्टियों की सरकार बनाना नहीं है। यह तो व्यवस्था का एक हिस्सा है। लोकतंत्र की सफलता क्या है ? लोकतंत्र का फल क्या है ? लोकतंत्र का फल है कि 130 करोड़ लोगों को अपनी-अपनी क्षमता और बुद्धि के अनुसार अपने आपको विकसित करने का मौका मिले और 130 करोड़ नागरिकों के विकास का फायदा देश को मिले, और देश का विकास हो, वही लोकतंत्र है, और अगर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता।

सफल लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में, उसको जो अधिकार मिले हैं, वो अधिकार निर्बाध रूप से उसको मिलते रहें। कानून ने जिन कर्तव्यों को, संविधान ने जिन कर्त्तव्यों को, जिस spirit से उस पर डाला है, उसका भी वो निर्वहन करता रहे और इन दोनों को मिलाकर देश का विकास होता रहे।

अगर कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है, और कानून और व्यवस्था ठीक रखने का काम देश की पुलिस करती है, देश की सुरक्षा में जुटे हुए सभी बल करते हैं और इन सभी बलों को, सभी पुलिस के संस्थानों को अपग्रेड करने का, उनको प्रशिक्षित करने का, उनकी खामियों को दिखाने का, बोले बगैर खामियों को सुधारने का काम BPR&D ने किया है।

कई बार मैं लोकतंत्र की बहस देखता हूँ। संसद, विधानसभा, न्यायालय, चुनाव आयोग, CAG, Vigilance Commission उसकी बहुत चर्चा होती है कि इन लोगों ने लोकतंत्र को सफल बनाया है। मैं बचपन से सोचता हूँ कि लोकतंत्र को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान, बीट के उस कांस्टेबल का है, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, वरना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। मगर न जाने किन कारणों से पुलिस की इमेज को ढेर सारे तरीकों से खण्ड-खण्ड करने का, कह सकते हैं कि अभियान भी चला। कुछ घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना, अच्छी घटनाओं को प्रसिद्धि नहीं देना। मैंने कई बार बोला, आज फिर से बोलना चाहता हूँ कि सबसे कठिन काम, पूरे सरकारी अमले में, अगर किसी सरकारी कर्मचारी का है, तो वह पुलिस के मित्रों का है।

मैंने कई बार दीपावली की रात को बाहर निकलते हुए देखा है कि कांस्टेबल ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं, मेरे मन में छोटा सा सवाल आता है, इसके लिए दीपावली नहीं है क्या? कोई बहन राखी बांधने के लिए जाती है और अपने भाई को राखी बांधकर सुरक्षित वापिस आती है, और वहां पर कोई कांस्टेबल को व्यवस्था करते हुए देखती हैं, तो बहन के मन में सवाल क्यों नहीं आता, कि इसकी बहन राखी नहीं बांधना चाहती क्या? होली हम सब लोगों के लिए त्यौहार है। पर पुलिस के लिए होली कानून और व्यवस्था संभालने का विषय है। चाहे जन्माष्टमी हो, ईद हो, मोहर्रम हो, हर जगह पर इतना कठिन काम शायद ही किसी सरकारी कर्मचारी का या अधिकारी का होगा। न काम के घंटे तय होते हैं, न काम में सुनिश्चितता होती है। मैंने देखा है इनके शरीर पर भी बहुत असर पड़ता है। मगर इसका acknowledgement बहुत कम हुआ है।

बहुत समय के बाद, जब कोरोना का कालखण्ड आया, मैंने देश के बच्चे से, छोटे से बच्चे से लेकर देश के प्रधानमंत्री जी को, पुलिस बल की सेवाओं को, कोरोना कालखण्ड में, पुरस्कृत करते हुए, शब्दों से नवाजते हुए देखा। प्रधानमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से पुलिस बलों पर जब पुष्पवर्षा करने का काम किया, तब मुझे लगा कि आज पहली बार पुलिस बल को, एक घटना के कारण, इतनी सारी प्रशंसा मिल रही है।

आज बालाजी यहाँ बैठे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पुलिस की इमेज बिल्डिंग के लिए BPR&D को विशेष काम करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ, यह आपके Mandate का हिस्सा है। कोरोना कालखंड में, देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी, और द्वारिका से लेकर आसाम तक, कई सारे पुलिस के लोगों ने, अलग-अलग स्तर के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसका एक अच्छा documentation होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री भी बननी चाहिए और एक यह अच्छा काम क्षणजीवी नहीं होना चाहिए। यह अच्छा काम समाज और देश याद रखे, इस प्रकार की व्यवस्था, BPR&D को, सब राज्यों के पुलिस बलों को साथ में रखकर, सब सीएपीएफ को साथ में रखकर करनी चाहिए। क्योंकि पुलिस की कुर्बानी, पुलिस का बलिदान, कम चर्चा का विषय होता है।

मगर आज यहाँ से, पीछे मुड़कर देखते हैं तो 35,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों ने, विभिन्न कामों के अन्दर, अपने जीवन का बलिदान दिया है। शायद, भारत के सभी युद्धों में 35,000 लोग नहीं मारे गए होंगे। मगर इन 75 साल में, 35,000 पुलिस के जवानों ने शहादत दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पुलिस स्मारक की रचना की है, और वो आज उन्नत होकर दिल्ली के बीच में है, जो बताता है कि पुलिस 35,000 बलिदानों के साथ, गौरव के साथ, आने वाले सालों में देश की सेवा में खड़ी है।

मैं जब पुलिस स्मारक पर गया था, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर देश भर के बलिदानों की एक डॉक्यूमेंट्री बने। हर राज्य से स्मारक देखने जब बच्चे यहाँ आएं तो उन्हें

documentary दिखायी जाए। लगभग 16 राज्यों ने, बच्चों के जो टूर होते हैं उसमें पुलिस स्मारक को समाहित कर दिया है, परंतु कोरोना के कारण बाद में टूर ही नहीं हुए। दिल्ली सरकार ने भी टूरिस्ट स्पॉट में इसको समाहित किया है। अब जब लोग आएंगे तो उनको दिखाने के लिए मैटिरियल चाहिए। सभी राज्य सरकारों से संकलन कर, BPR&D ये इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज का एक अच्छा मैटिरियल तैयार कर सकती है। सरदार पोस्ट से लेकर आज तक मैं मानता हूँ कि यह हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है, और BPR&D को ये काम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए।

आज मीराबाई यहाँ उपस्थित हैं। मेरी जब स्टेज पर उनसे मुलाकात हुई तो उनका भविष्य बहुत मंगल हो ऐसी शुभकामनाएँ दी हैं, और जब मीराबाई आपको पदक मिला, देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के छोटे से छोटे व्यक्ति तक, सब लोग आपके प्रदर्शन पर गर्व कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, और जब मैंने सुना कि आप ट्रेनिंग के लिए जाती थीं तब ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर जाती थीं। तब मुझे लगा कि खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कितना काम करना अभी बाकी है। मगर फिर भी आपने बहुत संघर्ष किया। आपके कोच भी आए हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और आपको आगे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। चाँदी से संतोष मत करियेगा, आप गोल्ड लेकर आइए। पूरा देश उसकी राह देख रहा है।

मित्रों, BPR&D एक ऐसा संस्थान है, जिसको किसी ढर्रे में नहीं फंसना चाहिए। BPR&D को चुनौतियों के हिसाब से अपने काम को बदलना चाहिए। क्योंकि BPR&D का मुख्य काम है चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल को तैयार करना। चुनौतियाँ स्थाई नहीं होती हैं। देश के समक्ष चुनौतियाँ बदलती रहती हैं। शायद BPR&D की स्थापना के वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो चुनौतियाँ होंगी, वो आज सबसे कम priority वाली चुनौती होगी। नीस्त-नाबूद तो नहीं होती है, मगर सबसे कम है।

आज साइबर अटैक सबसे बड़ी चुनौती है, ड्रोन अटैक सबसे बड़ी चुनौती है, नारकोटिक्स की स्मगलिंग सबसे बड़ी चुनौती है। फेक करेंसी सबसे बड़ी चुनौती है, हवाला रैकेट सबसे बड़ी चुनौती है। इन सबके लिए बदलती चुनौतियों को मापकर, इसकी तैयारी करना और विश्व भर में इन चुनौतियों को निपटने के लिए जो best practices हैं, इसका अध्ययन करके, हमारे देश भर के पुलिस बल को तैयार करना, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, इसको और मजबूत करने की जरूरत है। इसमें द्रुत गति लाने की जरूरत है, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है।

दो साल पहले मैं BPR&D में आया था। बेसिक पुलिसिंग, पुलिस रिफॉर्म और कई सारी चीजों पर मैंने बात की थी। मुझे खुशी है कि Modus Operandi से लेकर कई सारी चीजों को आपने जमीन पर उतारा है और आगे भी ले जा रहे हैं। मगर अभी भी मेरा आग्रह है कि, बीट सिस्टम को रिवाईव करे बगैर, बेसिक पुलिसिंग अच्छी नहीं हो सकती। बीट सिस्टम को रिवाईव करने के लिए, बीट सिस्टम को अपडेट करने के लिए, बीट सिस्टम का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के लिए, BPR&D को और काम करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ।

अभी मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार का गृह विभाग, CrPC, IPC और Evidence Act में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए ढेर सारी एक्सरसाइज कर रहा है। मुझे कहते हुए आनन्द है कि, कौमुदी जी के नेतृत्व में, BPR&D ने भी इस पर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। ढेर सारे लोगों से चर्चा करके, ब्यूरो ने 14 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 8 CPOs, 6 CAPF और सात गैर सरकारी संस्थानों से चर्चा करके, बहुत अच्छे तीनों एक्ट के अन्दर बदलाव के सुझाव भेजे हैं। इस पर काम चल रहा है। मगर मैं मानता हूँ कि, लास्ट टाइम मैं कहकर गया था, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको किया है और CrPC, IPC को ठीक तरीके से एमेंड करने के लिए वो बहुत सहायक होगें।

मित्रों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, तब BPR&D के चार्टर के अन्दर, मैंने कल चार्टर देखा था, कुछ चीजें जोड़ना भी चाहता हूँ। वैसे stretch करें तो चार्टर के अन्दर सीएपीएफ

है ही, परंतु जिस प्रकार की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में चुनौती आज हमारे सामने आई है, मुझे लगता है सीएपीएफ का आधुनिकीकरण, सीएपीएफ की ट्रेनिंग, उसका संचालन और ऑपरेशन्स स्किल बढ़ाने के लिए BPR&D को काम करना चाहिए। गृह मंत्रालय जरूरी होगा तो आपके चार्टर के अन्दर सुधार भी करेगा। मैं मानता हूँ कि ये काम BPR&D, बहुत अच्छे तरीके से, सबको साथ में लेकर कर सकती है और ये करना चाहिए। क्योंकि यह नितांत जरूरी है कि हमारी भू-सीमा और समुद्री सीमा दोनों सुरक्षित रहे और उसकी सुरक्षा में कोई कोताही न हो।

मित्रों मैं यहाँ पर आया हूँ तब इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि BPR&D को हर रिफ़ॉर्म का ग्राउंड पर कितना इम्पलीमेंटेशन हुआ है, इसकी एक व्यवस्था को institutionalize करना चाहिए। ये व्यवस्था institutionalize करे बगैर, हमारे सुधार प्रैक्टिकल हैं या नहीं, हमारे सुधार के लिए, हमें जिसके माध्यम से सुधार को लागू करना है, वो पुलिस बल को मोटिवेट कर पाए या नहीं कर पाए हैं, ये जान नहीं सकते। एक institutionalized व्यवस्था BPR&D में होनी चाहिए, कि देश भर में पुलिस रिफॉर्म जो होते हैं, वो जमीन पर कितने उतरते हैं। पुस्तक लिखना भी अच्छी बात है, सर्कुलर निकालना भी अच्छी बात है, आर एंड डी होना भी अच्छी बात है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात इसको जमीन पर उतारना होता है, तो इस पर भी BPR&D ने एक institutionalized व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ढेर सारे काम किए हैं। हमने वैधानिक ढांचे को सुदृढ करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ढेर सारे कानून हमने बदले हैं। समयानुकूल करे हैं और इसमें लॉ एन्फॉर्समेंट एजेंसी को बल मिले इस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। जम्मू और कश्मीर की धारा 370 और 35(ए) को निरस्त करना, अभी CrPC, IPC का पूरा परिवर्तन का काम हमने हाथ में लिया है। काम बहुत बड़ा है, दो साल से चल रहा है। साइबर सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं और "मिनिमम गवर्नमेंट, मेक्सिमम गवर्नेंस", के मोदी जी के सूत्र को गृह विभाग ने चरितार्थ करने का स्पिरिट के साथ प्रयास किया है। ये मैंने जो कहा ये चार लिंब के तहत, एनआईए

एक्ट में हमने संशोधन किया। शस्त्र अधिनियम में बदलाव किया। यूएपीए कानून में बदलाव किया। धारा 370 और 35(ए) को समाप्त किया।

NCORD के माध्यम से चार स्तरीय संरचना निर्माण कर नारकोटिक्स पर नकेल कसने के लिए, एक अभियान की शुरुआत की है, और मैं बहुत मन से, अच्छे भाव से कह रहा हूँ कि देश भर की पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विगत 25 साल में सबसे ज्यादा नारकोटिक्स, इन दो सालों के अन्दर पकड़कर, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। मगर इसके लिए ढेर सारे संस्थागत प्रयास किए गए।

पूर्वोत्तर के अन्दर बहुत सारे समझौते किए गए। एनएलएफटी का समझौता, शरणार्थियों का पुनर्वसन, बोडो शान्ति समझौता और आज 4 बजे ही कार्बी आंगलोंग के साथ समझौता होना है। लगभग 3700 हथियार-बंद कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मेनस्ट्रीम में आने का काम किया है। आप कल्पना कर सकते हो 3700 लोग हथियार के साथ जंगल में जी रहे थे। ये दो साल के अन्दर सरेंडर हुए हैं और हमारा लक्ष्य है कि, जो हथियार डालेगा, उनसे संवाद करके, हम उसको मेनस्ट्रीम में लाने का पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे। जिनके हाथ में हथियार हैं, उसके लिए पुलिस अपने तरीके से जवाब दे सकती है, इसमें भी कोई रोक-टोक नहीं। मगर जो हथियार डालकर डायलॉग करना चाहते हैं, संवाद करना चाहता है, उसके लिए रास्ते खुले हैं और सारे उग्रवादी संगठनों के साथ अलग-अलग स्तर पर बात चल रही है।

जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को नीचे तक पहुँचाने का, पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, तीन स्तरीय लोकतंत्र को लागू करके, चुनाव कराकर, डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर की जनता में percolate करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के अन्दर लोकतंत्र के मायने कुछ एमपी और कुछ एमएलए तक सीमित नहीं हैं। हर गाँव के पंच, सरपंच हैं, हर तहसील पंचायत का बोर्ड है, हर जिला पंचायत का बोर्ड है। लगभग 22 हजार लोग इस व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। यह मोदी जी की सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना, एफएसएल यूनिवर्सिटी की स्थापना और आपराधिक न्याय प्रणाली का सीसीटीएनएस के साथ इंटीग्रेशन करने का काम हुआ है। आईसीजेएस

की तीन प्रणालियाँ सीसीटीएनएस, e-Prison और e-Court लगभग पूर्ण तैयार हैं, देश में योगदान करने के लिए, और अन्य दो प्रणालियाँ e-Prosecution और e-Forensic इसके लिए भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।

गुजरात में National Academy for Costal Policing की भी स्थापना हुई है। साइबर सुरक्षा में I4C, आज अपने तरीके का, एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर, साइबर क्राइम को रोकने के लिए बना है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को देश को समर्पित किया जा चुका है और इसे पॉपुलर बनाने की जरूरत है। बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, और नेटग्रिड भी शायद कोरोना न होता, तो अब तक राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री कर चुके होते। मगर मुझे आशा है कि कुछ ही समय में नेटग्रिड को भी देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिग पोर्टल बना कर, हमने बहुत अच्छा एक प्रयोग किया है। एफसीआरए में भी आमूल-चूल परिवर्तन कर, एफसीआरए के माध्यम से जो पैसा देश को अस्थिर करने के लिए आता था, उस पर नकेल कसने का महत्वपूर्ण काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।

मित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की आंतरिक सुरक्षा देश का पुलिस बल संभाल रहा है, देश की सीमाओं की सुरक्षा, हमारे सीएपीएफ संभाल रहे हैं, और मैं ढाई साल तक इस विभाग में काम कर, सुनिश्चित हूँ कि, जिस मुस्तैदी के साथ हमारे सीएपीएफ बॉर्डर को संभाल रहे हैं और जिस मुस्तैदी के साथ हमारा पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा को संभाल रहा है, हम बहुत सलामत हाथों में हैं। मगर चुनौतियाँ बदलती हैं, चुनौतियाँ बढ़ती हैं, बढ़ती हुई और बदलती हुई चुनौतियों में, चुनौतियों को पार कर, दो कदम अस्थिरता फैलाने वालों से आगे रहना, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसमें BPR&D का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।

अगला एक दशक सुरक्षा की दृष्टि से, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का हमने लक्ष्य रखा है। ढेर सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं।

ढेर सारे रिफ़ॉर्म, इकोनॉमिकी साइड पर भी हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर देश का तेजी से बढ़े, इसलिए पॉलिसी के माध्यम से भी, ढेर सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं करेगा, ऐसे हमें सोचना नहीं चाहिए, और हमने सभी चुनौतियों का आकलन कर, देश भर के पुलिस बल और हमारे सीएपीएफ को हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि उसमें BPR&D का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग का जो कंसेप्ट हमारे सामने रखा है। उसको जमीन पर उतारना हमारा काम होना चाहिए।

मैं फिर से एक बार 51 साल तक BPR&D का जो योगदान है, समस्त पुलिस बलों के बीच में को-ऑर्डिनेशन का, उनके ट्रेनिंग का, उनके अपग्रेडेशन का और चुनौतियों को meet करने के लिए, कई सारे अभ्यास करने का, ये जो BPR&D का योगदान है, इसकी सराहना करता हूँ और आशा रखता हूं, 51 साल से आज आपका नया 50 साल शुरू हो रहा है, जब 100 साल संस्था के होंगे, तब ये और Relevant होगी, और प्रासंगिक होगी, और योगदान कर पाएगी। ऐसा मुझे विश्वास है।

मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं राज्य और केंद्र में मिलाकर कुल 12 साल तक मंत्री रहा, और 12 के 12 साल, गृह मंत्री रहा हूँ। मैं कई सारे अफसरों को पोस्टिंग के बाद मिला हूँ। कई सारे अफसरों की पोस्टिंग का काम होता है। Call on करने का सिस्टम होता है, आते हैं, कई लोग मन से आते हैं, मन के बगैर आते हैं, सिस्टम के कारण आते हैं। मगर जब BPR&D या ट्रेनिंग या ऐसी जगह पर पोस्टिंग होती है, मैंने हँसते हुए किसी को आते नहीं देखा। बालाजी श्रीवास्तव को मन से आते हुए देखा है, और उन्होंने मन से कहा है कि BPR&D के काम को मैं बहुत मन से करूँगा। हर काम मन से करने से ही परिणाम मिलते हैं। बालाजी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, आपके बाकी के कार्यकाल के लिए, और आपके नेतृत्व में BPR&D आगे बढ़े और देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देती रहे, यही ईश्वर से अभ्यर्थना।

भारत माता की जय।

47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस

28 - 29 नवम्बर , 2019

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

समापन समारोह में

माननीय श्री अमित शाह जी

केंद्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार

का संबोधन

कृपया YouTube पर सुनने हेतु स्कैन करें

उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन

सत्यमेव जयते

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा दिनांक 28 - 29 नवंबर, 2019 को आयोजित 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, के समापन समारोह में माननीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह जी का संबोधन

आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। संगठन में लम्बे समय तक मेरे साथी रहे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभा रहे श्रीमान केशव प्रसाद मौर्या जी। लम्बे समय तक लखनऊ के प्रथम नागरिक के नाते सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के हृदय, लखनऊ को जिन्होंने संजोया है, डॉ दिनेश शर्मा जी, जो उप मुख्यमंत्री के नाते उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मुख्य सचिव, श्रीमान आर. के. तिवारी जी., डी.जी.पी., उत्तर प्रदेश, ओ.पी. सिंह जी, डॉ ए.पी. महेश्वरी जी, और हम सब जिनके निमंत्रण पर आज यहां पर आए हैं, BPR&D के डी.जी., श्रीमान कौमुदी जी, और सभी राज्यों और संघ प्रदेशों से पधारे हुए सभी भाईयों और बहनों।

आज 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉंग्रेस के समापन समारोह कार्यक्रम में आप सबसे मिलकर मुझे अत्यंत हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। पहले भी एक बार जब मैं गुजरात का गृहमंत्री था, तब गांधी नगर में यह काँग्रेस आयोजित हुई थी। तब उस वक्त, जो प्रतिनिधि के रूप में आऐ थे, उन सभी सज्जनों और देवियों का स्वागत करने का मुझे मौका मिला था। आज मैं आपके सामने, इस कार्यक्रम में देश के गृहमंत्री के नाते उपस्थित हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से फायदा होता है या समापन समारोह कार्यक्रम में। कई बार, आप जो विचार रखते हैं, जब आप की काँग्रेस समाप्त हो जाती है, सांईस कॉंग्रेस समाप्त हो जाती है, तो विचारों का क्या उपयोग ? समापन के अन्दर की गई बातों का क्या उपयोग ? जो कार्यक्रमों के विज्ञान पर अभ्यास कर रहे हैं ऐसे लोगों ने मुझे कई बार कहा। मगर मैं हमेशा मानता हूँ कि समारोह के बाद ही शुरूआत होती है। जो मंथन हुआ

है, इसके implementation की शुरूआत समारोह के बाद ही होती है। इसलिए अच्छा समापन समारोह में ही जाना होता है। जब मुझे निमंत्रण मिला, तब मैंने भी तय किया था, कि 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस के समापन समारोह में ही मैं जाऊँगा। और ये जो BPR&D का काम है एक दृष्टि से समायोजन का काम है, Best Practices के exchanges का काम है। समस्याओं को ढूंढने का काम है, समस्याओं के समाधान पर चिंतन करने का काम है, उसका समाधान ढूंढ़ने का काम है, और जो समाधान ढूंढते हैं वे practical रूप से बीट तक लागू हो इसकी चिंता करने की जिम्मेदारी BPR&D की है। उसके Mandate को ध्यान से पढ़ें तो BPR&D के Mandate का और BPR&D के सारे वर्ष के काम को नीचे तक पहुंचाने का अगर कोई जरिया है तो मैं मानता हूँ कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस है।

कई सालों से आप, 1960 से लेकर अब तक, ये करते आए हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि एक अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस सिर्फ इस विषय पर करनी चाहिए कि 1960 से 2019 तक जितने भी resolutions पारित किये, जितने भी papers इसमें रखे गये, इनका हुआ क्या ? अगर चिंतन ही करते रहेंगे, और इसको circulate ही करते रहेंगे, तो फायदा क्या ? एक Science Congress तो विशेष पुलिस साईंस काँग्रेस बुलानी चाहिए जिसके अंदर 1960 से 2019 तक जितने भी papers यहाँ पढ़े गये हैं या रखे गये हैं, जिस पर विचार - विमर्श हुआ है, जितने विषयों पर R & D करने की जरूरत हुई, R & D हुई, इसके implementation के part पर क्या हुआ ? मैं मानता हूँ, इस पर एक गहन विचार करने की जरूरत है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर Internal Security भी गृह मंत्रालय का Mandate है, मगर केवल भारत सरकार के गृह मंत्रालय का Mandate नहीं है। हमारे संविधान ने Federal structure को स्वीकार किया है और law & order की जिम्मेदारी राज्यों पर है। परन्तु Internal Security को एक holistic approach से अगर देखें तो Internal Security में ढेर सारी चीजें आती हैं- सरहदी सुरक्षा आती है, घुसपैठ आती है, fake currency आती है, cyber हमले आते हैं, हथियारों की, पशुओं की, मानवों

की तस्करी आता है, Narcotics व्यापार आती है। ढेर सारी चीजें ऐसी आती हैं, जो कि सिर्फ State Police नहीं कर सकती। यह coordination के बगैर नहीं हो सकता। भारत के गृह मंत्रालय की भी सीधे जिम्मेदारी है कि, coordinator के रोल की जिम्मेदारी अदा करके, सारे राज्यों के साथ मिलकर, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के बीच में जो समन्वय है, उसको सुचारू रूप से नीचे ले जाएँ।

आज, जब हम सब यहां बैठे हैं तब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि घुसपैठ, narcotics control, नक्सलवाद, आतंकवाद, तीनो प्रकार की तस्करी, fake currency और routine law & order, सब करते - करते शायद हम लोगों को भी, जो Police force से आते हैं, जो Police force के लोग यहाँ बैठे हैं, जो नीति निर्धारण और नेतृत्व का काम करते हैं, उनको भी मालूम नहीं है कि आज जिस सफलता को हम देख रहे हैं उसके लिए 35 हजार से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गवाई है। अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तब जाकर यह देश सुरक्षित हुआ है। तब जाकर हमारी सीमाओं से लेकर अंतिम बीट तक सुरक्षा का अनुभव एक आम नागरिक कर सकता है।

केन्द्र में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक भव्य पुलिस स्मारक का निर्माण हुआ है। सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है, गृह सचिव ने सभी डीजी और Chief Secretary को पत्र लिखा है। क्या पुलिस स्मारक को अपने-अपने राज्यों में हम पुलिस चेतना का केन्द्र बना सकते हैं क्या ? आप सभी लोग अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर हैं, हमारा दायित्व है कि जनता का पुलिस को देखने का नज़रिया और पुलिस का जनता को देखने का नज़रिया दोनों में बदलाव लाना चाहिए। पुलिस का ठट्ठा करना, मजाक करना बहुत सरल बात है। कोई कार्टून बनाएगा, तो कोई बड़ी तोंद वाला पुलिस दिखा देगा, कोई हिन्दी पिक्चर के अन्दर उसका मजाक उड़ा देगा, मगर कोई सेवा ऐसी नहीं है जहां पर 35 हजार से ज्यादा जवानों ने शहादत दी है। इसका गौरव एक - एक Constable के अन्दर हम खड़ा कर सकते हैं क्या ? देश की 130 करोड़ की जनता को पुलिस को देखने के नज़रिये में बदलने में इसका हम उपयोग कर सकते हैं क्या ? देश की जनता को यह अनुभूति

करानी पड़ेगी कि जब एक भाई अपनी बहन के घर में राखी बन्धवाने के लिए जाता है तो Police constable traffic की चिंता करता है। जब आप अपने बच्चों के साथ दीपावली में पटाखे जलाते हो, तो Police constable उस दिन भी law & order की चिंता करता है। जब आप परिवार के साथ होली का लुत्फ उठाते हो, होली के त्यौहार को मनाते हैं, तब वह चिंता करता है कहीं दंगे तो नहीं हो जाएंगे।

Minus 43 degree temperature से 43 degree temperature तक की विषम परिस्थितियों के अंदर हमारे अर्धसैनिक बल सीमाओं को संभाल कर रखते हैं। मैं मानता हूँ कि यह नज़रिया बदलने की जिम्मेदारी यहां पर जो बैठे हैं, देश भर के जो पुलिस अधिकारी बैठे हैं, उनकी है। आप सब उच्चस्थ पदों पर बैठे हैं, एक - एक Constable के मन में ये गर्व खड़ा करना और राज्य की जनता के एक - एक व्यक्ति के, एक - एक नागरिक के मन में पुलिस के प्रति सम्मान की भावना खड़ी करना, ये हमारा primary दायित्व है। जब तक ये नहीं कर सकते हम Internal Security को ढंग से नहीं संभाल सकते। ये परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी BPR&D जैसे संगठनों की भी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की घटना हो तो घटना में first respondent की जिम्मदारी पुलिस की होती है। सबसे पहला टकराव पुलिस से होता है और जो first respondent की जिम्मेदारी उठाता है उसके प्रति जनता का सम्मान बनाना ये हमारा primary दायित्व है। आप सब के राज्यों में, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आप का delegation जाकर मिले। इस पर बल दिया जाना चाहिए।

राज्य के जितने भी बच्चों की टूर होती है उसके टूर के नक्शे पर हमारे पुलिस स्मारक का स्थान हो। आप के राज्य के अन्दर सबसे अच्छी जो घटनाएं law & order की, पुलिस के बलिदान वाली हुई हैं, लोगों की बड़ी जनहानि बचाने की हुई है, उनकी एक documentary बनाकर हम पुलिस स्मारक को भेज सकते हैं। बहुत सारे visitors आते हैं, दिखाने के काम में आती है। हर सप्ताह हम इसको change करके दिखाना चाहते हैं, मगर material नहीं है। अब जितने भी विदेश के महानुभव आते हैं, हम उनकी एक visit वहां पर रखें। अभी Uzbekistan के रक्षामंत्री आए थे, गृहमंत्री आए हुए थे, डेढ़ घन्टे तक वे पुलिस स्मारक पर

रहे। श्रीलंका के राष्ट्रपति भी गये। इसको समृद्ध करना, हमारे बलिदान की गाथाओं से, हमारे अच्छे performance की कहानियों से, हमारी best practices से, उसका दायित्व हमारा है। मुझे लगता है हमें इसको करना चाहिए।

मित्रों, Internal Security का दायरा बहुत बड़ा है। जैसा मैंने आगे कहा, 15 हजार किलोमीटर से ज्यादा जमीनी सरहद, 7500 किलोमीटर का Coastline Border है और चारों ओर से भारत को मुश्किल में रखने के जब प्रयास हो रहे हों, तब हमें जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। Internal Security भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि 3 बिंदु ऐसे हैं जिनसे Internal Security को भारत में मजबूत बनाने की जरूरत है। सबसे पहला, 130 करोड़ का Market है। Global Economy 130 करोड़ का Market स्वाभाविक रूप से ताकतवर destination के रूप में भारत को दुनिया के बाजार के बीच में रखता है। मोदी जी के आने के बाद अपने अर्थतंत्र को गति देने की प्रक्रिया चली है। 2004 में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तालिका में 11वें नंबर पर थी। सिर्फ 5 साल के अंदर 11वें नंबर से 7वें नंबर पर आ गई है और हमारा लक्ष्य है, 2024 तक इसे 5 trillion dollar की economy बनाकर एक से तीन नंबर के अंदर जाने का हमारा लक्ष्य है। जब हम ये प्रयास करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें रोकने के लिए ढेर सारी शक्तियाँ activate होंगी तो उनका सामना कौन करेगा- हमें करना है। Cyber attack को, fake currency को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है- हमारी है। Cyber attack और fake currency के बड़े - बड़े scams, उसका अच्छा investigation, professional investigation और दण्डित करने की प्रक्रिया का सुधार करना, ये जिम्मेदारी हमारी है। तभी जाकर मोदी जी का जो स्वप्न है, हमारे अर्थतंत्र को गति देने का, वह हम सिद्ध कर पायेंगे। तो पहला कारण है, हमारी Internal Security को चुस्त और दुरूस्त करने का कि हम 5 trillion dollar की economy बनना चाहते हैं और 130 करोड़ का बाजार आज पूरी दुनिया के लिए एक lucrative centre, आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। यहां कानून और व्यवस्था, Internal Security, अगर अच्छी नहीं होगी तो ये कभी नहीं हो सकता। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, 15 हजार किलोमीटर

की Land Boundary और 7500 किलोमीटर की Coastline है। और पड़ोसी के बारे में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। आप सब को मालूम है, मगर पड़ोसी तो हम बदल नहीं सकते, हमें चुस्ती में बढ़ोत्तरी करनी पड़ेगी। वहां से जो आतंकवाद के बीज बोए जाते हैं, उसको कोई space न मिले, उसको कोई जगह न मिले। हमारी Border Security को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए, Border Security पर तैनात अर्धसैनिक बलों और State Police के बीच में coordination अभेद्य होना चाहिए, कि हवा भी बीच में से ना जा सके। इस प्रकार का अभेद्य coordination करने की जिम्मेदारी हमारी है। और तीसरा, हमारा देश बहुत सारे धर्म, बहुत सारी भाषाएँ, बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे पहलुओं से बंधा हुआ है। एक ओर तो हमें इसका गौरव है। हमारे देश की पहचान ही विविधता में एकता की है, परन्तु उसके साथ - साथ vulnerability बढ़ती है। दुश्मन को जगह मिलती हैं। भेद खड़ा करने की, दुश्मन को जगह मिलती है, Cyber attack से अलग-अलग प्रकार के मतभेद देश की जनता के बीच खड़े करने की, उसकी रोकथाम करना, कठोरता के साथ इसको खत्म करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ, ये तीनों चीजों के कारण, हमारी Internal Security बहुत महत्वपूर्ण बनती है, और बहुत कठिन भी बनती है।

मित्रों, हमारे पास Democracy, Demography Dividend है। और इसीलिए हम भारत की Destiny को बदलना चाहते हैं और मुझे भरोसा है, मोदी जी के नेतृत्व में हम बदल सकते हैं। मगर उसकी पूर्व शर्त है कि 21वीं सदी के भारत की आंतरिक सुरक्षा को हम चुस्त-दुरूस्त रखें और इसके लिए अपने आप को तैयार करें। और वो केवल भारत सरकार नहीं कर सकती। जब तक देश का हर राज्य और संघ प्रदेश एकवाक्यता के साथ इसमें contribute नहीं करता, ये बदल नहीं सकती।

हमारी Policing के अंदर भी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। श्री कौमुदी ने मुझे quote करके कहा, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि Police Reform से ज्यादा Policing में Reform की जरूरत है। और हमारे Reform की दिशा को थोड़ा मोड़ने की जरूरत है और ये सिर्फ technology से नहीं हो सकता। जब मन नहीं जुड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं इतने

बड़े भवन के अंदर आया, UP Police का। मगर भवन के अन्दर अगर काम करने वालों के मन में भावना नहीं है, तो ये भवन कभी भी अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। भवन परिणाम नहीं दे सकते। भवन के अंदर काम करने वालों की भावना ही परिणाम दे सकती हैं। और ये परिवर्तन हमें करना पड़ेगा।

ये Science Congress formality बनकर नहीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक होनी चाहिए, परिवर्तन की परिचायक बननी चाहिए। और वह तभी बन सकती है, जबकि यहां जो चर्चाएं होती हैं, इसको spirit से बीट तक लागू करने के लिए हम आगे बढ़ें। मित्रों, मैं आप को बताना चाहता हूँ कि Motivation वाली Leadership के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले देश में हर जगह उत्तर प्रदेश के law & order के चर्चे होते थे। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और देश के गृहमंत्री के नाते, दोनों के नाते, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के law & order को बहुत - बहुत सुधार करके, एक अच्छे राज्य का उदाहरण दिया। एक Motivated Leadership क्या कर सकती है, इसका एक उदाहरण है और आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, एक प्रकार से लीडर हो, अपने क्षेत्र के लीडर हो। अपने क्षेत्र को Leadership देनी है। 50 हजार से 60 हजार का पुलिस बल (मैं एवरेज कह रहा हूँ) उसका Leader कौन होता है ? Senior most Police officer होता है और मैं इसीलिए कहता हूँ कि BPR&D की ये इस प्रकार की meetings है जो Best Practices के आदान प्रदान के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म होती है अगर हम इसको जारी रखें तो यहां पर जो पेपर श्रुत हुए हैं, और यहाँ पर जो चीजें कही हैं, इसको spirit के साथ अपने राज्य के अनुकूल जो चीजें हैं, वह बीट तक ले जाने के लिए पहल करें और सफलता तभी मिल सकती है, जब हर राज्य के अंदर Constable से लेकर DGP के बीच Policing के दृष्टिकोण और Policing के implementation के लिए एकवाक्यता होनी चाहिए। एक टीम के नाते, पूरी force काम करे, तभी जाकर हमें सफलता मिल सकती है। मैं मानता हूँ कि इसकी बहुत बड़ी जरूरत है।

मित्रों, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। IPC और CrPC के अन्दर आमूल-चूल परिवर्तन का है। Arms Act भी बदल रहे हैं। इसी सत्र के अन्दर Narcotics के बारे में भी कानून में संशोधन कर रहे हैं। और बाद में CrPC और IPC में भी बदलाव लाएंगे। क्योंकि दृष्टिकोण ही अलग हैं, CrPC और IPC की रचना तब हुई थी, जब एक देश जो हमारे उपर शासन करता था उसने गुलाम देश पर अपनी कानून और व्यवस्था का शासन करना था। उसकी priority नागरिक नहीं था। उसकी priority हमारा देश नहीं था। उनकी priority अपना शासन चलाना था। अब हम स्वतंत्र हो गये हैं। हमारे अपने नागरिक हैं। वो approach नहीं चलेगी। और जब तक कानून नहीं बदलेगा - CrPC और IPC नहीं बदलेगी - तो approach नहीं बदलेगी। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मानव वध से बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है ? आप के यहाँ धारा 302 है, लेकिन उससे पहले खजाना लूटना, राज्य के सामने विद्रोह करना, ये सारी दफाएँ आती हैं। तो, priority क्या है ? ये इंगित करता है कि ब्रिटिश शासन की तो ये priority हो सकती है, पर सार्वभौम के साथ, गौरव के साथ जीने वाले हिंदुस्तान की भारत की ये priority नहीं हो सकती। हमारी priority देश का गरीब से गरीब व्यक्ति ही है। और इस spirit के साथ अगर इसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सुझाव दीजिए। वैसे तो BPR&D ने अपना बदलाव का मसौदा बनाकर गृह मंत्रालय को भेज दिया है, मगर मुझे कोई जल्दी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चर्चा कीजिए। Police Inspector और Police Sub - Inspector तक, जो रोज practically इसका उपयोग करते हैं, वहां से सुझाव आने चाहिए। इसको सरल कैसे बनाएं, इसको सुचारू कैसे बनाएं, इसको लोकान्मुख कैसे बनाएं ? इसके अंदर सज़ा सबसे ज्यादा करा पाएँ, इस तरह के प्रावधान कैसे add किया जाए, ये सारी चीजों को देख कर एक complete परिवर्तन करना चाहिए। ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन, रोज - रोज नहीं होते। कभी - कभार, सदी में एकाध बार होते हैं और मैं मानता हूँ कि आप लोगों को मौका मिला है कि सदी में एक बार जो परिवर्तन होने वाला है, इसके अंदर contribute करने का किसी ने मौका दिया है। ये नीचे से सुझाव मंगाईये, उसके लिए committee बनाईये, इसका screening

करिए, इसको दफाओं में धाराओं में ढालिए और बाद में conclude करके सुझाव भेजिए। मैं मानता हूँ कि इसके अन्दर आप सब ने, हर राज्य ने, हर प्रदेश नें, और जिनको अनुभव है, चाहे वो अर्धसैनिक बल में तैनात हों, उन सभी को contribute करना चाहिए। इस पवित्र प्रक्रिया से हमारा CrPC और IPC का परिवर्तन होना चाहिए। बाद में, उसको website पर भी रखने वाले हैं, बहुत सारे वकीलों से भी और बहुत सारे जजों से भी इसके सुझाव मंगाने वाले हैं, बाद में जाकर सरकार निर्णय लेगी। परन्तु मेरा आग्रह है, जो implement करने वाले हैं, वो अगर सुझाव देते हैं तो ये सुझाव बहुत उपयोगी सुझाव होंगे।

दूसरा सबसे बड़ा काम हम करने जा रहे हैं - एक रक्षा शक्ति University बनाने जा रहे हैं- Centre में। और जिन राज्यों में Police University नहीं है, वहाँ पर उनका एक College खुलना चाहिए, ताकि जिस बच्चे ने तय किया है कि मुझे Professional Policing में ही जाना है तो उसको बाकी सब पढ़ाने की, सिखाने की जरूरत है मगर सीमित मात्रा में उसको पुलिस विषय का विशेषज्ञ बनाने की जरूरत है। तो 10 वीं कक्षा के बाद, कोई बच्चा अपना career बना सकता है इस विषय में हर राज्य में इसका एक College होगा और Central University होगी और उसके अंदर सभी प्रकार की विधाओं को, Forensic Science को भी, पढ़ाया जाएगा। कानून भी पढ़ाया जाएगा, prosecution भी पढ़ाया जाएगा, investigation भी पढ़ाया जाएगा और पुलिस स्टेशन को कैसे अच्छा रखना, कैसे चलाना है, coordination, दूरसंचार ये सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब ये कानून लेकर University की स्थापना भारत सरकार करे- जहाँ - जहाँ पर भी ऐसी विशेष University नहीं है, University के संलग्न College खोलने के लिए आप लोगों को पूरा योगदान देना है। Facilitation यहाँ की होगी force यहाँ होगी, परन्तु एक College आप के राज्य में भी बनाइये, जिससे एक विशेष रूप से तैयार किया हुआ कार्यबल, लंबे समय के बाद, हमारे पास उपलब्ध हो। और उनको नौकरी देने के लिए interview में priority भी दें। जो यहाँ से निकल कर आएगा, क्योंकि वह तो readymade material है, जिसकी training आपको करानी ही नहीं है। और, अगर ये नौकरी बनने का ज़रिया बनता

है, तो मैं मानता हूँ कि सभी चाहेंगे कि वे university के अंदर admission लें और एक अच्छा Police Officer पहले से बनकर वहाँ पर जाएं। मुझे लगता है कि इसमें आप सबने अपने - अपने राज्यों को तैयार भी करना पड़ेगा।

एnitiative लेने वाले हैं। National Forensic Science University को बनाने जा रहे हैं। केन्द्र सरकार की मंशा है कि सज़ाओं के अभी जो percentage है, सजा दिलाने का जो पर्सेंटेज है, वो बहुत कम है। Conviction रेट को देखें तो दयनीय है। इसको कैसे अच्छा करें ? मैं मानता हूँ कि ढेर सारी कठिनाइयाँ हैं। कोर्ट के अंदर केस सालों साल पड़े रहते हैं। जो Investigation करता है, बाद में तो कहीं और चला गया होता है। केस उसको पूरा याद भी नहीं होता है। Prosecution की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। परन्तु हमने क्या प्रयास छोड़ देना चाहिए ? जो आदती गुनहगार है, उसको जब तक सज़ा नहीं कराते हैं, तब तक अच्छे लोगों में संदेश जाना असंभव है। और सज़ा कराने का प्रमाण हमें बनाना ही पड़ेगा। और इसीलिए forensic science को हमने (जिस अपराध में) 7 साल और उससे ज्यादा सजा है, तो इन सब में FSL को compulsory करना है। Circular तो आज ही हो सकता है। मैं कर भी सकता हूँ। आप सब को advisory भी दे सकता हूँ। मगर manpower कहाँ है। FSL के इतने विशेषज्ञ ही नहीं हैं। तो उसको बनाने पड़ेंगे। हर जिले के अंदर एक FSL branch बनानी पड़ेगी, क्षेत्र के अंदर IG तक की जो आप की रेंज होगी। हर राज्य में एक अलग - अलग व्यवस्था है। मगर एक रेंज की जगह पर एक छोटी FSL laboratory और राज्य के मुख्यालय में बड़ी FSL laboratory और trained manpower हों। ये करना है तो Forensic Science की पढ़ाई - लिखाई किये हुए बच्चे हमें चाहिए, युवा चाहिए। इसलिए हम Forensic Science University बनाना चाहते हैं। इसमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक इसकी affiliated college आपके राज्य में खुलनी चाहिए, जो बहुत कम खर्चे में खुल सकती है। किसी कॉलेज को convert भी कर सकते हैं। किसी भी Science College को convert भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि इतना तो आपका प्रभाव है। आप के senior most, पाँच Police officer मिलकर, मुख्यमंत्री जी के पास जाएँ और

बोलें कि Forensic Science का एक कॉलेज हम अपने यहां बनाएंगे। मुझे लगता है कि कोई मुख्यमंत्री ना नहीं बोलेगा। क्योंकि, उसकी भी इच्छा है कि अंततोगत्वा राज्य के अंदर अच्छा law & order हो। परन्तु, इसके लिए हमें initiative लेना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि FSL University, हमारा सजा कराने का जो प्रमाण है उसमें बहुत बढ़ोत्तरी करेगा। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसमें भी आप का सहयोग अपेक्षित है और मिलना भी चाहिए।

मित्रों, narcotics देश की आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है। और, दुर्भाग्य से, इसकी स्थिति ऐसी है कि Centre में Narcotics Bureau, State Narcotics Bureau, District Headquarters Police और बीट इसके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। Revenue Department भी देखता है, pharmacy वाले भी देखते हैं। ऐसा "गौंधण" करके रख दिया है। जो मराठी है, वह मेरे शब्द का प्रयोग समझ पाएगा। ऐसा "गौंधण" करके रख दिया है कि इसकी सटीक कार्यवाही हो ही नहीं सकती। भारत सरकार इसमें भी सुधार करने जा रही है। Narcotics Bureau के पूरे structure को बदलना चाहिए। मगर, उसके साथ आपके Narcotics Bureau को बीट स्तर तक की व्यवस्था का भी एक Model बनाकर हम आपको देंगे। Advisory Form में भेजेंगे क्योंकि हमारे संविधान के अंदर हम advisory दे सकते हैं। मगर वह advisory form में जो model आता है उसको आपके राज्य की परिस्थिति के अनुरूप बदलकर जरूर implement करने का प्रयास करें। क्योंकि जिस देश की नस्ल खोखली हो जाती है, वह देश कभी दुनिया का leader नहीं बन सकता। और मैं आपको कहता हूँ, मित्रों दुनिया का leader बनने का भारत का समय आ गया है। हमें कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए, narcotics पर पूर्ण control होना चाहिए। सारे अर्धसैनिक बल हैं, वो इसको रोकेंगे। उसके raw material की खेती पर भी हम दबाव बनाएँगे। Chemical Narcotics हैं, उस पर भी हम अलग कानून लेकर आ रहे हैं। Coordination की व्यवस्था होगी। एक्ट भी कठोर होगा और इसमें prosecution के लिए भी एक trained manpower भी हम राज्यों के लिए देने के लिए सोच रहे हैं। अच्छे वकील भी देंगे, जो

इसमें पारंगत हों। एक ही विधा के अन्दर जिन्होंने specialization किया हो। मैंने सभी law university के dean को पत्र लिखा है कि आप के यहां एक अलग डिपार्टमेंट खुलना चाहिए और उसमें specialization करने वाले बच्चों की सूची हमें दें। क्या असंभव है अगर पुलिस ठान ले तो मैं आप को आज भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मजाक उड़ाना है उड़ा ले। आज भी, जितना भी गांव में शोर - शराबा होता है, दंगा होता है, वहाँ पर दो constable, हाथ में लाठी लेकर पहुंचते हैं, तो लोग कहते हैं, पुलिस आ गई, भागो, और शांति हो जाती है। ये credibility आज भी हमारी है। उसको आगे बढ़ाने का काम है। मैंने कई बार देखा है, मेरे सार्वजनिक जीवन में, सिर्फ दो ही Constable डंडा लेकर आते हैं और तलवार लेकर दंगा करने वाले भाग जाते हैं, क्योंकि कानून आपके पीछे खड़ा है, व्यवस्था आप के पीछे खड़ी है, न्याय आपके पीछे खड़ा है और इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और Narcotics को control करने के लिए भी आपका सहयोग भारत सरकार को चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपका भी दायित्व है भारत सरकार को सहयोग देने का।

दूसरा Modus Operandi Bureau जब तक नहीं बनाएंगे, हम कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पर control नहीं कर सकते। FIR के registration होने के साथ ही Bureau के पास इसकी gist आनी चाहिए। और उसके बाद जब सजा होती है तो इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए। और FSL के Psychological Department का भी ये दायित्व है कि Modus Operandi Bureau स्थापित करे। एक प्रकार की ही चोरी करने वाले लोग, उसको पकड़ने के लिए क्या व्यवस्था है ? एक प्रकार से ही लूट करने वाले लोग, उसको पकड़ने की क्या व्यवस्था है ? इस तरह से Modus Operandi का प्रयोग करके, ढेर सारे गुनाह को होने से पहले रोकने में हमें सफलता मिल सकती है। अगर हम इसका विश्लेषण ही नहीं करेंगे, तो सफलता नहीं मिल सकती। तो Modus Operandi Bureau के विचार को भी मैं चाहूंगा कि कुछ राज्य adopt करें, इसको cultivate करें। और सफलतापूर्वक अपने राज्यों के अन्दर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें।

एक मेरा दूसरा आग्रह है कि Prosecution, Director की व्यवस्था राज्य स्तर पर करना चाहिए। केस में परिणाम क्यों नहीं आया ? सरकारी वकील Public Prosecutor कितने date मांगते हैं ? क्यों date मांगते हैं ? जब तक उनकी जवाबदेही तय नहीं करेगा कोई, तब तक केसों में सजा होने की कोई संभावना ही नहीं है। और वह तभी हो सकता है जब कोई exclusive Director, Prosecution, के नाते बड़े - बड़े cases में हत्या है, बलात्कार है, शस्त्र के साथ लूट है, बड़ी धाण हैं, ये सारी चीजों के केसों में सजा हो, इसकी चिंता किसी को headquarters पर बैठकर करना चाहिए। और प्रावधान है, कानून में। मगर हम करते नहीं क्योंकि हमें लगता है कि हम पर watch dog है। ये हम पर watch dog नहीं है। जो व्यवस्था को जीर्ण - शीर्ण कर दे, उस पर watch dog है। हम तो नहीं चाहते व्यवस्था जीर्ण - शीर्ण हो। कोर्टों के अंदर हमारा पक्ष रखने वाले क्या कर रहे हैं, इस पर हमारी नजर होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ? मैं मानता हूँ, होनी चाहिए। तो मेरा अनुरोध है, सभी लोगों से आपके राज्यों के अंदर Director, Prosecution, को भी आप अलग प्रकार से initiative लेकर एक institutionalized रूप देने का प्रयास करें। हो सकता है कि दो - तीन साल लगेंगे, पाँच साल लगेंगे, मगर जब भी सफल होगा, आप retire भी हुए होंगे तो आप को संतोष होगा कि, अपने समय में मैंने जो काम किया था, आज मेरे राज्य की बहुत अच्छी सेवाएँ institution दे रहा है। पूरे भाव के साथ करना चाहिए।

जेलों के मैनुअल का upgradation बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी जिम्मेदारी Police force की है। जेल को अलग department बनाने से कुछ नहीं होता। By and large, यह पूरा law & order के दायरे में आता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी Police force की है। तो जेलों के manual के upgradation के लिए भी मेरा आप सब से आग्रह है कि एक टीम बनाईये और जल्दी से काम करना चाहिए। Weapons, ballistics, traffic and transport, design, uniform और बीट को पुनर्जीवित करना, परेड को नियमित करना, खबरी प्रणाली, foot march, community policing, ये सारी चीजों पर नये - नये,

छोटे - छोटे प्रयोग करने के लिए, नीचे स्तर के अफसरों को हमने promote करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। और जो ये नये प्रयोग करता है, एक district में एक नया SP, युवा SP, जो बीट प्रणाली को पूरी जीवित कर लेता है, तो उसको कुछ - न - कुछ appreciation senior officers की ओर से मिलना चाहिए। कोई अपने जिले के बैंड को ढंग से बना लेता है और हर शनिवार और रविवार को जिले के मुख्यालय के अलग - अलग स्थानों पर पुलिस का बैंड कूच करे बगैर, 10 मिनट तक राष्ट्र भावना वाले गीत बजाकर वापस आ जाए, और वो आकर्षण का केन्द्र बन जाए, घर से अभिभावक अपने बच्चों को लेकर वहाँ खड़े रहते हैं, तो आप मानना कि वह SP ने अच्छा काम किया है। उसको प्रेरणा दीजिए। Dog Squad और Horse, इन सबकी चिंता करनी चाहिए। इस सबका अपना - अपना एक रोल है। गाड़ी आने से policing मजबूत नहीं होती। Movement fast होता है। पुलिस के पुराने जितने भी अंग हैं, मैं मानता हूँ कि उनका review, मैं मानता हूँ कि आप के स्तर पर ही करना चाहिए। चंडीगढ़ पुलिस ने बीट के लिए बहुत अच्छा प्रयोग किया है। इसको और भी अच्छा किया जा सकता है। मेरा आग्रह है कि सभी लोग उसको एक बार देखें। गृह मंत्रालय ने अभी - अभी बहुत सारे initiative लिए हैं। NIA Act में सुधार, UAPA में सुधार किया है। धारा 370 हटाना, रामजन्म भूमि के बाद एक अच्छी कानून और व्यवस्था कायम रखने का परिचय आप सबने दिया। कश्मीर के अन्दर इतना बड़ा फैसला आने के बाद भी आज तक पुलिस की गोली से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मैं मानता हूँ कि ये भारतीय पुलिस की सबसे बड़ी सफलता है। इस सफलता के दौर को हमें आगे ले जाना है। और सफलता के दौर को आगे ले जाना है तो ढेर सारी चीजें व्यवस्था के लिए हम करने वाले हैं। CrPC और IPC के amendment पर बिल लाने वाले हैं। NRC का implementation करने वाले हैं। CrPC और IPC में आमूल - चूल परिवर्तन करने वाले हैं। FSL University का बिल आएगा। रक्षा शक्ति University पर बिल आएगा। ढेर सारे बिल आएँगे। तो मुझे लगता है, ये बिल तब तक सफल नहीं होते जब तक spirit खड़ा करने का काम यहाँ मेरे सामने जो leaders बैठे हैं उनके अंदर नहीं हैं।

मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि ऐसा ही दो दिन का सम्मेलन सिर्फ अभी तक के शोध papers पर और लिए गये निर्णयों पर करना चाहिए। पहले तो problem पर research करना चाहिए, उस पर study paper invite करना चाहिए। इसमें जो सुझाव आए हैं, उनको classify करना चाहिए। उसके आधार पर नीति में परिवर्तन करना चाहिए। उसका trial क्रियान्वयन करना चाहिए। और बाद में उसको review कर, उसको स्थायी रूप देना चाहिए। ये प्रक्रिया जब तक नहीं करते हैं, ये पिकनिक के अलावा कुछ नहीं होगा। माफ करना मेरे शब्दों को। हमेशा ही टेंशन में रहते हैं। हर रोज मुख्यमंत्री जी फोन कर देते हैं। हर रोज MLAs / MPs फोन कर देते हैं। अच्छा है दो दिन लखनऊ में हूँ। तो फोन आएगा तो कह देंगे लखनऊ में हैं। क्या ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए ? हमारा उद्देश्य व्यवस्था में सुधार करना है। हमारा उद्देश्य व्यवस्था को परिणामों तक पहुंचाना है। अगर ये हम करना चाहते हैं, तो मैंने जो कहा, research, शोध पेपर, सुझाव नीति में परिवर्तन, इसके क्रियान्वयन, उसका review, और बाद में उसका स्थायित्व। ये अगर हम नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि बहुत परिणामदायी conference नहीं रहेगी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने SMART Police की कल्पना की है, आप लोगों तक पहुँचा ही होगा। मगर फिर से एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ S से Sensitive, M से Modern, A से Alert, R से Reliable और T से Tech. Savvy. SMART Concept को नीचे Constable तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और, मोदी जी की कल्पना का विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत तभी बन सकता है, जब कानून और व्यवस्था अच्छी हो, Law & Order अच्छा हो और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। इस जिम्मेदारी के बोझ से नहीं मगर इस जिम्मेदारी के दायित्व के भाव को समझ कर हम यहां से जाएँ, ये मेरी प्रार्थना है। आप सबको अनंत-अनंत शुभकामनाएं !

जय हिन्द !

ब्यूरो का 49वां स्थापना दिवस

28 अगस्त, 2019

नई दिल्ली

माननीय श्री अमित शाह जी

केंद्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार

का संबोधन

कृपया YouTube पर सुनने हेतु स्कैन करें

उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन

सत्यमेव जयते

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 49वें स्थापना दिवस पर दिनांक 28 अगस्त, 2019 को माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन

आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित, जिनके निमंत्रण पर आज मैं यहाँ आया हूँ, श्रीमान कौमुदी जी, मेरे साथी गृह राज्य मंत्री श्रीमान जी. किशन रेड्डी जी, भारत सरकार ने अभी-अभी जिनको नियुक्त किया है, हमारे गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, आई. बी. के डायरेक्टर श्री अरविन्द कुमार जी, श्री देशमुख जी, अरोड़ा जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, भाइयों और बहनों।

आज मैं यहाँ Bureau of Police Research & Development (BPR&D) की 50वीं सालगिरह पर स्थापना दिवस पर आप सबके सामने उपस्थित हूँ इसलिए सबसे पहले मैं हृदय से शुरुआत से अब तक जिन्होंने इस संस्था को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, आगे बढ़ाए रखने के लिए, निरन्तरता बनाए रखने के लिए और अपग्रेड करने के लिए जिन-जिन लोगों ने योगदान दिया है, उन सभी को भारत सरकार की ओर से हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।

बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी संस्थाओं को चलाने का मुझे अनुभव भी है। कोई भी संस्था चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, जब 50 साल तक निरन्तर चलती है तो हमें समझना चाहिए कि उसके काम में भी दम है और काम करने वालों में भी दम है। जहाँ तक BPR&D का सवाल है, न सिर्फ 50 साल चली, बल्कि 50 साल तक अपनी प्रांसगिकता बनाए हुए चली। अपनी रिलेवेन्सी को बनाए रखना 50 साल तक, किसी भी संस्था के लिए ये सरल काम नहीं है। पुलिस एक विभाग है, उसको चलना ही है क्योंकि सरकार की ओर से चलना एक संवैधानिक रोल है मगर BPR&D जैसी संस्थाओं का, जिनका सीधा संवैधानिक रोल न होते हुए भी उस रोल को निभाना, पुलिस को मॉडर्नाइज़

करना, उसको अपग्रेड करना, इसके लिए अपनी रिलेवेन्सी बनाए रखना, मैं मानता हूँ बहुत कठिन है। मैं हृदय से, फिर से एक बार आप सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

सरकार की जब चर्चा चलती है तो ज्यादातर डेवलपमेन्ट के कामों की चर्चा होती है, वित्त विभाग के अलग-अलग प्रकार के विकास के कामों की चर्चा होती है परन्तु जब से स्टेट नाम की institution अस्तित्व में आई, तब से राज्य के सबसे पहले किसी उपांग की शुरुआत हुई थी तो वह लॉ एण्ड ऑर्डर था। लॉ एण्ड ऑर्डर सबसे पहले शुरू होने वाला विभाग था। राजस्व भी उसके बाद आया, न्याय भी उसके बाद आया, समाज कल्याण भी उसके बहुत देर से जुड़ा। डेवलपमेन्ट भी बाद में जुड़ा, नगर रचना भी बाद में जुड़ी। राज्य का अस्तित्व आने के बाद सबसे पहला कोई विभाग शुरू हुआ तो कानून और व्यवस्था हुआ, पुलिस विभाग हुआ और इसके बल पर ही सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त हुआ। इसलिए मैं, आज BPR&D के सभी आला अफसर जो यहाँ पर बैठे हैं, सबको कहना चाहता हूँ कि मोदी जी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में देश को ले जाना चाहते हैं, दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में देश को ले जाना चाहते हैं और हम सबको भरोसा है कि मोदी जी का जिस प्रकार का नेतृत्व है, देश जरूर वहाँ पहुँचेगा। परन्तु वहाँ पहुँचने के लिए निहायत जरूरी है कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को हम बरकरार रखें और इसे बेहतर, बेहतर, बेहतर बनाते जाएं, चाहे वह आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो। जब आंतरिक सुरक्षा के लिए जो आज के जमाने की हमारे सामने challenges हैं, जब तक उन challenges के सामने खड़ा रहने का दमखम नहीं रखते, ये 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के स्वप्न को सिद्ध करना नामुमकिन है और ढेर सारी चुनौतियाँ आज हमारे सामने है और इसलिए मैं BPR&D के सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों के लिए पुलिस बल को सुसज्जित करने में आपकी अहम भूमिका है।

Modernization, Training, कई सारे काम आप देखते हैं और National Think Tank का आपका रोल है। हमारा देश संघराज्य है, संघीय ढांचा हमने स्वीकार किया है। राज्य अपने-अपने तरीके से चलते हैं। पुलिस और लॉ एण्ड ऑर्डर राज्य का विषय है, परन्तु ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त मोटिवेशन वाली और मोटिवेट करने वाली लीडरशिप हर राज्य की

पुलिस को प्राप्त हो। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। मेरा भी अनुभव है, मैं देखता हूँ कि कई बार मोटिवेशन देने वाली और मोटिवेटेड लीडरशिप जब मिलती है, तब तो सब अच्छा कर लेते हैं, मगर कई बार नहीं मिलती है तब ग्राफ नीचे आने लगता है। BPR&D का ये दायित्व है कि ग्राफ कभी नीचे न आए, ग्राफ ऊपर, ऊपर, ऊपर जाता जाए और वो तब होगा जब व्यवस्थाओं को हम institutionalize करते हैं। व्यवस्थाओं को संस्थागत करना चाहिए। व्यवस्थाओं को कानून के महज एक नियमों के बंधन में बांधने की जगह स्वतः व्यवस्था एक nature बननी चाहिए। व्यवस्था एक स्वभाव बननी चाहिए, पूरे पुलिस बल का, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक का। जब व्यवस्था एक स्वभाव बनती है, तो उसके लिए कोई पुस्तक बनाने की जरूरत नहीं है, कोई पुस्तक छापने की भी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं कि पुस्तकें निरर्थक हैं। मगर हमनें वो आइडियल कंडीशन की ओर जाने का लक्ष्य रखना चाहिए कि नेचुरल कोर्स में समय के साथ-साथ देशभर के सभी राज्यों के कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक का पुलिसिंग का कांसेप्ट एक हो, एकवाक्यता हो, सबको अपनी-अपनी भूमिका की स्पष्टता हो और ये काम एक detailed ट्रेनिंग के बगैर नहीं हो सकता और ये काम BPR&D को थिंक टैंक के नाते करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।

हमारे देश में पुलिस की शुरुआत कोतवाली से हुई, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने थानेदार बनाए। भारतीय पुलिस की मूल नींव रखने का काम किया मगर उस वक्त पुलिस की रचना के पीछे राज्य का रक्षण करने की सोच थी। जनता का रक्षण करने की सोच नहीं थी। उनका राज्य यहां बना रहे इसलिए पुलिसिंग की व्यवस्था हो रही थी। पुलिस का एप्टीट्यूड भी उसी तरह से बनाया था। आप IPC, CrPC देखिए, तो पहले राजद्रोह आता है, उसके बाद में मानव वध आता है। यह mentality बताता है legislator की, कि जो रेलवे को नुकसान करेगा, वो गुनाह ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद में मानव वध आता है। सरकार के खिलाफ कोई द्रोह करेगा, वो गुनाह ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद मानव वध आता है। वह उनकी मेन्टिलिटी को बताता है। अंग्रेजों के समय में जो पुलिस की रचना थी, उसका मूल आशय उनके राज्य को बरकरार रखना था। आजादी के बाद सरदार पटेल ने, हमारे पहले गृह मंत्री ने उसको एक अलग shape देने का प्रयास किया, एक अलग कांसेप्ट हम लोगों के

सामने रखा। पहले क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, आजादी के लिए जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होते थे, उसको दबाने के लिए पुलिस का उपयोग होता था। उनके खजाने की रक्षा के लिए होता था। सरदार पटेल ने पहली बार पुलिस को लोगों की सेवा के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए और लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक पहल सरदार पटेल ने की। मुझे बहुत संतोष भी है, आनंद भी है कि इतने सालों के बाद 60 दशक के बाद हमारी पुलिस ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है।

मेरा बचपन गांव में बीता। कभी भी कोई थोड़ी बहुत भी चहल-पहल हो जाती थी, हुड़दंगे जैसा हो जाता था, गांव में सब लोग इकट्ठा हो जाते थे और सिर्फ दो हवलदार हाथ में डंडा लेकर आते थे, 500 लोगों में शांति हो जाती थी कि पुलिस आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। ये भरोसा आज पुलिस ने खड़ा किया और ये भरोसे को आगे ले जाना है। जमाना बदल रहा है, हमारी चुनौतियां भी बदल रही हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए, पुलिस को मॉडर्नाइज़ करने की दिशा में भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।

आज, मैं आप सबको याद कराना चाहता हूँ कि देश की आंतरिक सुरक्षा को बल देने के लिए देश को आंतरिक रूप से सुरक्षित करने के लिए अब तक लगभग 34,800 से ज्यादा पुलिस जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान, अपनी जान का बलिदान दिया है, तब जाकर पुलिस की साख बनी है, जिसको हमें आगे बढ़ाना है। जब काम करते हैं, तब मालूम नहीं होता परन्तु एक व्यक्ति का बलिदान जब होता है, तब हमें इसकी अहमियत मालूम होती है कि 34,800 से ज्यादा लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश को आंतरिक रूप से सुरक्षित करने के लिए दिया है और इसी का नतीजा है कि पुलिस की साख बनी है। मेरा मानना है कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए।

पुलिस रिफॉर्म्स एक बहुत लम्बी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। चुनौतियां जैसे बदलेंगी, इसको अलग तरीके से पुलिस रिफॉर्म को हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा, मगर पुलिसिंग में रिफॉर्म बहुत बड़ा कांसेप्ट है, उसको नए सिरे से BPR&D को डिजाइन करना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म और पुलिसिंग में रिफॉर्म दोनों में बहुत

अंतर है और मुझे लगता है कि पुलिसिंग में भी रिफॉर्म की जरूरत है। पुलिस का नजरिया, और कानून और व्यवस्था को टैकल करने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। गृह मंत्रालय अभी इस पर अलग-अलग स्तर पर काम कर रहा है। कुछ योजनाएं मेरे मन में भी है, कुछ अधिकारी भी इस पर काम कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि इस दिशा में भी BPR&D को सोचना चाहिए। कानून में जो जरूरी बदलाव है, वो सरकार करेगी ही, उसमें कोई कोताही सरकार की तरफ से नहीं की जाएगी परंतु पुलिस में और पुलिसिंग के अंदर रिफॉर्म, वह BPR&D की जिम्मेदारी है और इस पर नई दृष्टि से, नए दृष्टिकोण से सोचना चाहिए।

अभी कुछ दिन पहले कौमुदी जी मुझे मिलने आए थे, मैंने उनको कहा है कि CrPC और IPC के अंदर आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए देशभर में एक कंसेलटेटिव प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सबके सजेशन लेने चाहिए और इन सबके सजेशन का डाक्यूमेंटेशन करके वो गृह विभाग को एक अपना संकलित सुझाव भेजें। CrPC और IPC में अंदर बहुत समय से बदलाव नहीं हुआ है, इसको करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो कम्प्यूटराइजेशन हुआ है हमारे यहां, वो भी कई जगह पीसमील में हुआ है। कुछ राज्यों ने एनआईसी का कम्प्यूटराइज प्रोग्राम आने से पहले ही अपने यहाँ कम्प्यूटराइज कर दिया था। हमारे ही राज्य गुजरात, उसमें एनआईसी के आने से पहले ही कम्प्यूटराइजेशन हो चुका था। कुछ लोगों ने जो पहले कम्प्यूटराइजेशन किया है, उसमें काफी कुछ अच्छा रखा है, अब एनआईसी का भी सॉफ्टवेयर आ गया। मुझे लगता है कि सारी जगह जो अलग-अलग काम हुआ है, इसको एक बार फिर से, ऊपर से किसी को देखने की जरूरत है और वो BPR&D ही कर सकती है, इसका मुझे भरोसा है। इस दिशा में भी BPR&D को आगे बढ़ना चाहिए।

हम नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों राष्ट्रीय स्तर पर बनाएंगे। इसकी संरचना ऐसी रहेगी, इसके एफिलेटेड कॉलेज हर राज्य के अंदर होंगे और 12वीं कक्षा के बाद कोई भी बच्चा, जिसको तय है कि मुझे पुलिस में ही जाना है, अब उसको आर्ट्स पढ़कर, कॉमर्स पढ़कर या साइंस पढ़कर बहुत ज्यादा फायदा नहीं। उसने तय कर लिया कि मेरा करियर मुझे पुलिस में बनाना है, आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाना है। पुलिस से मतलब अलग-अलग सशस्त्र बल भी आते हैं तो इसकी शुरू से ही ट्रेनिंग सही दिशा में हो और उसको

जब वो एग्जाम देने जाए, तो उसका वेटेज भी मिलना चाहिए। इस प्रकार की एक सुगठित व्यवस्था देश भर में होनी चाहिए। एक मसौदा BPR&D ने भेजा है। अभी थोड़े ही दिनों में इसको कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और इस बात पर निर्णय लिया जाएगा परंतु फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस कॉलेजेज की दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए BPR&D ने खूब त्वरित गति से काम करने की जरूरत है क्योंकि जो केसों में सजा कराने का हमारा अनुपात है, वो आज साफ अर्थ में दयनीय है। आज के जमाने में ऐसा नहीं चल सकता। इसको सुधारने की जरूरत है और यह तभी सुधर सकता है जब जांच को फॉरेंसिक साइंस का वैज्ञानिक सपोर्ट मिल जाए। अगर फॉरेंसिक साइंस और वैज्ञानिक सपोर्ट के साथ चालान किया है, चार्जशीट किया है तो जज के सामने और डिफेंस के लॉयर के सामने बहुत ऑप्शन नहीं रह जाते हैं। तब सजा कराने का अनुपात हम सुधार पाएंगे। सभी केस में फॉरेंसिक विजिट को हम कम्पलसरी करना चाहते हैं, पर विचार से क्या होता है, इसके लिए मैनपावर चाहिए, मैनपावर नहीं है हमारे पास, तो पहले मैनपावर क्रिएट करने की व्यवस्था करनी होगी। फॉरेंसिक साइंस के सब्जेक्ट में ही एक्सपर्ट स्टूडेंटस और नए अफसर मिलें, इसकी समयानुकूल व्यवस्था करनी होगी और मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ही यह कर सकती है । फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में एक प्रयोग हुआ है, सफल प्रयोग हुआ है। आज गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से निकला हुआ एक भी ग्रेजुएट नौकरी के बगैर नहीं है। डिमांड - सप्लाई गैप समझने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो देश की रिक्वायरमेंट है और जो बच्चे तैयार होकर आते हैं, इसके बीच में बड़ा गैप है, इस गैप को हमें भरना पड़ेगा और एफएसएल का जितना उपयोग हम बढ़ाएंगे, कानूनी तौर पर कम्पलसरी करेंगे, उतना ही हमें गुनाहगारों को सजा दिलाने में सफलता मिलेगी और इसके बाद ही गुनाह करने की मानसिकता कम हो पाएगी। इस दिशा में भी BPR&D को काम करना चाहिए।

जेल का मैनुअल भी अपग्रेड हुआ है, मैनुअल मैंने देखा है मगर आज भी जेल विभाग के कर्मचारियों और, अधिकारियों के ट्रेनिंग की और कैदी के प्रति उनके अप्रोच की पूरी दिशा को बदलने की जरूरत मुझे लगती है। जेल का काम शिक्षात्मक नहीं है, भले दंड संहिता नाम दिया गया हो, मगर जेल का काम शिक्षात्मक नहीं हो सकता, शिक्षणात्मक हो सकता है। जेल

के अंदर जो व्यक्ति आता है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाकर बाहर भेजने की दिशा में हमारा अप्रोच होना चाहिए। हमारा आशय उसको दंडित करना नहीं है, उसको दंड देकर बाकी सारे लोग गुनाह न करें और जिसको दंड मिला है उसको जीवन में एक नया मौका मिले, इस प्रकार की जेल की व्यवस्था के लिए, एक बार आमूल-चूल परिवर्तन करके, नए सिरे से देखने की जरूरत है।

मुझे लगता है कि जो मॉडर्नाइज़ेशन का काम आप सात स्तंभों के अंदर कर रहें हैं, वेपन्स, बैलिस्टिक, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड डिजाइन, यूनिफॉर्म, लाइफसाइंस, इलेक्ट्रॉनिक इक्वीपमेंट्स, इन सातों विभागों के अंदर थोड़ा सामंजस्य रहे। एक-दूसरे का सभी के साथ रिलेशनशिप है तो इसको स्तम्भ मानने की जगह एक रिलेटिव दृष्टि से मॉडर्नाइज़ेशन की पूरी स्कीम हमारी बने, इस दिशा में भी देखना चाहिए। अब तक जो प्रस्ताव आते हैं मॉडर्नाइज़ेशन का, मेरा पढ़ने लिखने का स्वभाव है, मैंने बारीक दृष्टि से देखा है। बजट आया है, उसको खर्च करना है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच से मॉडर्नाइज़ेशन को देखना चाहिए। कम्पलीट पुलिसिंग, कम्पलीट पुलिस की व्यवस्था एक राज्य में करने के लिए 10 साल का राज्य का मॉडर्नाइज़ेशन प्लान बनाना चाहिए और इसी प्रकार से सम्पूर्ण देश को पुलिसिंग की दृष्टि से कम्पलीट करने के लिए 10 साल का एक प्लान बनाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तभी जाकर मॉडर्नाइज़ेशन सही मायनों में सफल होगा और ये बात बहुत जरूरी है क्रिमिनल और क्रिमिनल माइंडेड लोगों से पुलिस चार कदम आगे रहनी चाहिए, पीछे नहीं रहनी चाहिए और वह तभी हो सकता है जब मॉडर्नाइज़ेशन को एक हॉलिस्टिक व्यू लेकर हम देखें ।

अब कोई थर्ड डिग्री का जमाना नहीं है। इंवेस्टीगेशन के लिए भी हमने साइंटिफिक तरीकों को उपयोग करना पड़ेगा। फॉरेंसिक साइंस के अलावा भी। मैने कल ही कौमुदी जी को कहा कि एक 'मॉडस् आपरेंडी ब्यूरो' के लिए आप सोचिए जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा और हर राज्य में भी एक 'मॉडस् आपरेंडी ब्यूरो' बनाना चाहिए, जो गुनाह करने की पद्धति और उनकी मेंटिलिटी दोनों का स्टडी करके, इसको खत्म करने की दिशा में हम आगे जाएं। मुझे लगता है इस दिशा में भी BPR&D को काफी काम करने की जरूरत है । परेड, खबरी प्रणाली, फुटमार्च, कम्यूनिटी पुलिसिंग, ये सारी चीजें अपनी जगह पर महत्व रखती है। मॉडर्न

पुलिस का ये मतलब नहीं कि थाने के अंदर आपको सूचना देने वाला कोई व्यक्ति न हो। टेलीफोन टैपिंग से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर प्रिवेंटिव पुलिसिंग करनी है, गुनाह होते हुए रोकना है तो ये पुरानी जो परम्परा है, उसको आज के समय के अनुसार ढालकर फिर से व्यवस्था में लाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा उपयोग है। बीट सिस्टम को भी फिर से एक नई ताकत देने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है और ये पुलिसिंग के जो पुराने तरीके थे, वो सारे तरीकों को, समय बहुत गया है, नई जरूरतें भी आई हैं, मगर कॉन्सेप्ट को हम रिजेक्ट न करें, विचार को रिजेक्ट न करें, विचार को बदलें, कॉन्सेप्ट को बदलें, आज के समयानुकूल बनाने का काम करें। इन सभी चीजों पर BPR&D को कभी न कभी विचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।

फॉरेंसिक साइंस का, निर्भया फंड आने के बाद उस तक ही सीमित रह जाए ऐसा न हो, ऐसा मुझे कभी-कभी भय लगता है। BPR&D का काम है कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, गृह मंत्रियों को सेंसीटाइज़ करके बजट पुलिस विभाग के लिए बढ़े, एक आइडियल पुलिस विभाग बनने के लिए उनके राज्यों में क्या-क्या पूर्तता करने की जरूरत है, इसको भी रिसर्च करके, सर्च करके, एनालिसिस करके BPR&D दे, तो काफी राज्यों को फायदा हो सकता है। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं परंतु अब तक जो हुआ है वो संतोष व्यक्त करने जैसा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि BPR&D ने 50 सालों में देश की पुलिसिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया है वो देश के आंतरिक सुरक्षा में अतुलनीय है, अद्वितीय है और ये संस्था जितनी मजबूत बनेगी उतनी ही हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत बनेगी।

प्रधानमंत्री जी ने पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट रखा था, एक फिल्म में बताया गया है मगर मैं मानता हूं कि हम आतंरिक सुरक्षा के काम से जुड़े हुए सभी लोग एक ऐसे वातावरण को निर्मित करें कि भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में लाने का जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, मोदी जी का स्वप्न है, इसको हम अपने कुछ ही समय के अंदर पूरा होते हुए देख सकें और आंतरिक सुरक्षा की सारी चैलेंजस जिसको हम पार कर सके, इसका सामना कर सकते हैं, चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। इस प्रकार की पुलिसिंग देश में BPR&D के तत्वाधान में होगी और

ये जो थिंक टैंक का काम है उसके रोल को भी थोड़ा मजबूत करने की जरूरत है। मैं जब बैठूंगा आप लोगों के साथ, तो बताउंगा, परन्तु प्रोएक्टिव रोल BPR&D को करना चाहिए और अपने दायरों को भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इतना ही मुझे आज कहना था।

मैं आज, जिन लोगों को पदक मिले हैं और विशेषकर छोटे-छोटे राज्यों से, नॉर्थ-ईस्ट से एवं अलग-अलग स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों को मिले हैं, मैं सबको बहुत- बहुत बधाई देता हूँ। BPR&D जो 50वें साल में एन्टर कर रही है, 100वें साल में देश का कोई गृह मंत्री आए तब BPR&D का इतिहास और रोल दोनों बहुत उज्ज्वल हो, स्वर्णिम हो, ऐसी मैं शुभकामना देकर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

जय हिन्द !

51st FOUNDATION DAY FUNCTION
OF
BPR&D

04 September, 2021
New Delhi

Address by

Shri Amit Shah

Hon'ble Union Home Minister
& Minister of Cooperation,
Government of India

Please scan for speech on YouTube

Promoting Good Practices and Standards

बालाजी श्रीवास्तव, भा.पु.से.
महानिदेशक

Balaji Srivastava, IPS
Director General

Tel. : 91-11-26781312 (O)
Fax : 91-11-26781315
Email : dg@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

Bureau of Police Research & Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-8, Mahipalpur,
New Delhi-110037

Hon'ble Union Home Minister and Minister of Cooperation, Government of India, Shri Amit Shah graced the 51st Foundation Day Function of the Bureau of Police Research & Development (BPR&D), on September 4, 2021. Speaking on the occasion, the Hon'ble Minister flagged the milestones of the Bureau, and wished it well for the journey ahead.

Expanding the scope of BPR&D's mandate, the Hon'ble Minister underscored the need for including in its Charter, Issues relating to the CAPFs, Emerging Challenges of Internal Security, Concerns of Land and Sea borders, Augmenting of Police Image, Studying of Best Police Practices internationally, and Monitoring of Implementation of Recommendations at Ground Zero.

The Hon'ble Minister commended the Bureau for effectively anchoring Centre-State relations on key professional issues, including Police Training, Research, Modernization and Incubation of ideas, among others. He called for augmenting its role further, as an emissary, on matters of professional policing.

The Bureau had organized the 47th All India Police Science Congress (AIPSC) on 28-29 November, 2019 in Lucknow and the 49th Foundation Day of the BPR&D on 28 August, 2019 at New Delhi. The Hon'ble Union Home Minister had graced both these occasions and addressed all the police forces in the country. The addresses of the Hon'ble Union Home Minister on these three occasions are published in this "Bureau Darpan" as a ready reference for invaluable guidance to all of us.

Balaji

(Balaji Srivastava)
Director General

Promoting Good Practices and Standards

सत्यमेव जयते

Address by the Hon'ble Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah on the occasion of 51st Foundation Day of Bureau of Police Research & Development on 04 September, 2021

Member of the Council of Ministers of Modi Ji, my colleague, Shri Nityanand Rai Ji, Home Secretary to the Government of India, Shri Ajay Kumar Bhalla Ji, DIB, Shri Arvind Kumar Ji, DG, BPR&D, Shri Balaji Srivastava Ji, Shri V.S.K. Kaumudi Ji, who has commanded the BPR&D for a very long time and maintained its momentum, Additional DG Shri Neeraj Sinha Ji, all brothers and sisters present in today's important program, virtually as well as in physical mode Greetings to all of you.

I have come here today on the 51st Foundation Day function of BPR&D. Many medals have been received by deserving officers of our police family for their excellent performance. Some institutions have also received trophies for outstanding contribution. Ms Mirabai, who has made the country proud, she has now become a member of the police family, she is also present here with us today. I congratulate everyone and appreciate their consistent hard work and loyalty. My greetings to all of them.

Friends, today, BPR&D is celebrating its 51st Foundation Day. Any organization, which maintains its relevance for 51 years in its field, means that its work has significance and relevance. BPR&D has proved both. I am associated with more than 80 institutions, ranging from small women's organizations associated with khadi work to the largest of institutions. It is a big challenge for any institution to maintain

its relevance because time keeps on changing and the institutions also need to change according to the time. It is only an institution, which changes itself according to times, performs continuously and works hard, that passes the test of time in its field. Probably very few from the general public, have known about the 51 years of BPR&D. I think the work of BPR&D is very important. That's why when I first came to BPR&D, I wrote in the visitor's book that **"Good policing cannot be imagined without BPR&D".**

Friends, BPR&D is also important from another point of view. In our federal polity, we have accepted the federal principles and structure, in which there is a Central Government, several State Governments and UTs. In the division of work, law and order is a State subject. When the federal structure has to be strengthened, then the link between the law and order agencies of all the States, the link between the police and its allied organizations is very important. For any country, the challenges come in various ways. There are Governments from different parties, different ideologies or different thinking. Sometimes regional parties are also there. Sometimes Governments at the centre are a coalition and sometimes it is a single party.

If Law and Order is to be strengthened to meet the challenges, then a nodal agency is needed to coordinate with all. In absence of such a nodal agency, the law and order of the country will be shattered. I believe that in the last 51 years, in terms of maintaining law and order, the BPR&D has discharged commendable role of the link agency connecting all the States in the country. Otherwise, it was impossible for the country to face the law and order challenges arising from different laws of different States, whether they were border States, land locked States or coastal States. It is not possible for the States to meet

these challenges all by themselves unless a central system assesses all these challenges and works day and night to upgrade India's police forces, while adopting global parameters and best practices. I believe that BPR&D has done this work very well for these 50 years. For this, I want to congratulate all the former Directors of the BPR&D, present here. My thanks to all of them.

Friends, after independence we adopted a republican democracy. Democracy is the very ethos of our country. If someone says that democracy came after August 15, 1947 or when we accepted the Constitution then it is not correct. Democracy is a part of our people's mindset. The concept of Panch-Parmeshwar has always existed in our villages. Thousands of years ago, the Yadavas had a republic in Dwarka. There were many republics in Bihar. Individual freedom and freedom of expression are the core values of democracy. Freedom of an individual is directly related to law and order. Democracy does not mean only voting for a party and forming a government. This is only one aspect of the system. What is the meaning of democracy? What is the essence of democracy? Democracy means that 130 crore people of the country should get a chance to develop themselves according to their capabilities and intelligence, and the country in turn, should get the benefit of the development of 130 crore citizens. If the law and order situation is not good then democracy can never succeed.

For a successful democracy, it is very important to ensure security of the common man. Individuals' rights must be ensured in accordance with the law. The individuals too, should discharge their constitutional duties in the right spirit. Together, this will ensure the development of the country. However, if the law and order is not good, then democracy can never succeed. It is the police of the country that maintain law

and order, alongwith the other forces engaged in the security of the country. BPR&D has been the driving force in upgrading and training all these police forces.

I watch debates on democracy, in Parliament. It is discussed that the Courts, Election Commission, CAG and Vigilance Commission have made democracy successful. However, I say this not because I am the Home Minister, but since childhood, I have thought that the biggest contribution in making democracy successful is by the beat constable of police, who ensures the security of the citizen. Otherwise, democracy could not have succeeded. But for unknown reasons there is a campaign going on for harming the image of police in many ways. Some unnecessary events are highlighted, while the good deeds are not glorified. I have said it many times earlier and today again I want to say that the most difficult task in the entire government is of my friends from the police.

On Diwali night, while going out, many times, I have seen a constable on duty. A question comes to my mind, is Diwali not for him? When a sister goes to tie Rakhi to her brother and comes back safely after tying Rakhi but when she sees a constable making arrangements for law and order, why doesn't the question come to her mind whether his sister would not want to tie Rakhi to him? Holi is a festival for all of us, but it is a matter of law and order for the police. Whether it is Janmashtami, Eid, Muharram, there will be hardly any government employee doing such hard work as the police.There are neither fixed working hours, nor any surety in work for the police. I have seen that this has harmful effects on their health but it has not been acknowledged enough.

When the Corona pandemic came, I saw that from a small child to the Prime Minister of the country, appreciated the services of the police forces during the Corona period. When the Hon'ble Prime Minister showered flower petals from the helicopter on the police forces, I felt for the first time that the police force is finally getting their much deserved praise.

Today Balaji is sitting here. I would like to tell him that the BPR&D needs to do special work for the image building of the police forces. I believe that this is a part of the Bureau's mandate. During the Corona pandemic, from Kashmir to Kanyakumari and from Dwarka to Assam, many policemen across the country, our officers and employees of different ranks have done a great job. It should be well documented. A documentary should also be made so that these good deeds are not lost sight of. This good work should be remembered by our society and the country. BPR&D should make such arrangements, with co-operation of police forces of all the States and CAPFs, because the devotion of police, and its sacrifices are not often discussed.

Today, when we look back, more than 35,000 police personnel have sacrificed their lives in the line of duty. Perhaps, these many people would not have died in all the wars of India, but in the last 75 years, 35,000 police personnel have been martyred. They have made the supreme sacrifice. They have laid down their lives for the country and that's why the Prime Minister of this country, Shri Narendra Modi Ji has created National Police Memorial in Delhi, a testament that the Indian Police with so many sacrifices, is steadfast in the service of the nation.

When I visited the National Police Memorial, I mentioned that a documentary of the great sacrifices from across the country should be made and it should be shown to the children when they come here. About 16 States have incorporated the National Police Memorial in children's tours. However, due to Corona, tours of children have not taken place. The Delhi Government has also included it as a tourist spot. When people come to the National Police Memorial, there should be good material to show them. By compiling material from all States, BPR&D can collate good material for the image building efforts. I believe that this is our duty and BPR&D should do it.

Today, Mirabai is present here. When I met her on stage, I wished her a very happy future. Mirabai, when you got the medal, every citizen including the Prime Minister of the country was proud of your achievement of winning the medal. When I heard that when you used to go for training, you had to take lift from truck drivers, then I realized, how much is yet to be done for the facilities for our players. You have struggled a lot. Your coach has also come, I want to felicitate him also and wish you all the best for good performances ahead. Don't be satisfied with Silver, bring the Gold, the whole country is waiting for that.

Friends, the BPR&D is an institution that should not get stuck in a pattern. The BPR&D should change its work according to the challenges. One of the main functions of the BPR&D is to prepare the police forces to meet the ever-changing challenges before the country. Perhaps the challenges of law and order at the time of the establishment of the BPR&D, may be of the least priority today. Today, cyber crimes, drone attack, smuggling of narcotics, fake currency, hawala racket etc. are the biggest challenges. You are doing very well to assess

the emerging challenges and studying the best practices to deal with these challenges across the world. You are doing very well to prepare the police forces across the country. I want to say that it needs to be sharpened further. It needs to be accelerated.

Two years ago, I visited the BPR&D. I spoke about basic policing, Police reforms and many other topics. I am happy to know that Modus Operandi Bureau has been set up and the BPR&D is taking it further. I insist that without reviving the beat system, basic policing cannot be improved. I believe that to revive and update the beat system, the BPR&D needs to do more work for technological up-gradation of the beat system.

At present, under the leadership of Modi Ji, the Home Ministry of the Government of India, is undertaking a lot of exercises to make fundamental changes in CrPC, IPC and Evidence Act. I am happy to say that in this regard, the BPR&D has made good contribution, under the leadership of Kaumudi Ji. After discussing with a lot of people, with 14 States, 3 Union Territories, 8 CPOs, 6 CAPFs and 7 Non-Government institutions, the Bureau has sent suggestions for making changes in these three Acts. Work is in progress. You have very well executed what I had mentioned in my last visit, and these suggestions would be very helpful in amending the CrPC and IPC properly.

Friends, I have seen the Charter of BPR&D yesterday. I want to add a few things under the Charter. In a way, CAPFs are already in the Charter. But the kind of challenges we face today in the security of borders, I think BPR&D should work for modernization, training and enhancing the operational skills of CAPFs. If necessary, the Ministry of Home Affairs will also make amendments within your Charter of

duties. But I believe that BPR&D can do this work very well by taking everyone together, because it is necessary that both our land and sea borders remain safe and there should be no lapse in security.

The BPR&D should institutionalize a system to know how many reforms have been implemented on the ground. We should assess whether our reforms are practical or not. Without an institutionalized system, we cannot know if we have been able to motivate the police force or not. Hence there should be an institutionalized system in the BPR&D to know as to how many police reforms all over the country are implemented on the ground. Writing a book is a good thing, issuing circular is also a good thing and R&D is also a good thing, but the most important thing is to get the reforms implemented on the ground. So, I think BPR&D should make an institutionalized arrangement on this too.

Friends, the government which is running under the leadership of Modi Ji, has done a lot of work for the internal security of the country. We have done a lot to strengthen the legal framework. We have changed many laws, amended laws according to time and we have made such arrangements which can strengthen the Law Enforcement Agencies. The abrogation of Article 370 and 35 (A) has been done. We have now taken up the task of complete transformation of CrPC and IPC. The work is huge, and going on for last two years. A lot of work has also been done for cyber security. The Home Department has tried to fulfil Modi Ji's formula of Minimum Government, Maximum Governance. We have amended the NIA Act, Arms Act, Changed the UAPA Act and abolished Article 370 and 35(A). We have started a campaign to crack down on narcotics by creating a four-tier structure through NCORD. In the last 2 years, the police and the Narcotics Control Bureau have

impounded large quantities of narcotics, much more than that in last 25 years. A lot of institutional efforts have been made for this.

Many agreements have been made in the Northeast, such as NLFT agreement, resettlement of refugees, Bodo Peace Agreement etc. Today at 4 o'clock, an agreement with Karbi Anglong is to be done. Around 3,700 armed cadres have surrendered and joined the mainstream. You can imagine, 3700 people lived in the forest with weapons. They have surrendered during last two years. Our goal is to communicate with all those who will lay down weapons, and to try to bring them into the mainstream. For those who have weapons in their hands, the Police can handle them in their own way. There is no restriction in this either. But all those who want to communicate, want to have dialogue after putting down arms, are welcome. Communication and talks are going on with all the militant organizations at different levels.

The work of promoting democracy among the people of Jammu and Kashmir has been done, by implementing three-tier democracy at Panchayat, Tehsil Panchayat, and Zila Panchayat, by conducting elections.The meaning of democracy in Kashmir is not limited to a few MPs and some MLAs. Every village has Panch, Sarpanch, every Tehsil Panchayat has a Board and every District Panchayat has a Board. 22,000 people are contributing to this system. This is a very big achievement of Modi Ji's Government. The establishment of Rashtriya Raksha University, the establishment of FSL University and integration of the criminal justice system with CCTNS has been done. Three systems of ICJS, i.e., CCTNS, e-Prison and e-Court are almost ready to contribute to the country and we are working fast for the other two systems, e-Prosecution and e-Forensics.

National Academy for Coastal Policing has been established in Gujarat. In cyber security, I4C has become a very important Centre to prevent cybercrime. The National Cybercrime Reporting Portal has been dedicated to the country and the need is to make it more popular. Even the NATGRID could have been dedicated to the nation by the Prime Minister if there was no Corona pandemic. But I hope that soon, the Prime Minister of the country will dedicate NATGRID to the nation. We have done a very good experiment by starting a licensing portal at the national level for private security agencies. By making major changes in FCRA, the Narendra Modi Government of the Bharatiya Janata Party has done the important work of curbing the money which used to come to destabilize the country.

Friends, I want to say that the internal security of the country is being handled by the police force of the country and security of the borders is being looked after by our CAPFs. After working for two and half years in this Department, I can say that the effectiveness with which our CAPFs are handling the borders and the promptness with which our police force is handling the internal security, we are in very safe hands. But the challenges change, challenges increase and with this, it should be our goal to overcome the challenges and stay ahead of those who are trying to destabilize us. The BPR&D can have a big role to play in this.

The next decade is going to be very important from the security point of view, especially from the point of view of Internal Security. The country is progressing under the leadership of Modi Ji. We have set a target of a 5 trillion dollar economy. Lots of reforms are being carried out. Lots of reforms are taking place on the economic front as well as in the infrastructure of the country to grow rapidly. Lots of reforms

are being done through policy also. We should not think, however, that no one would make any effort to stop this. After assessing all the challenges, the police forces across the country and our CAPFs should be ready to face every challenge and I believe that the BPR&D can have a big contribution in this regard. It should be our endeavour to implement on the ground, the concept of SMART Policing that the Hon'ble Prime Minister has put in front of us.

Once again, I appreciate the contribution made by BPR&D during 51 years for the coordination among all the police forces, their training, their up-gradation and undertaking exercises to overcome various challenges. From the 51st year today, your next 50 years are starting. When this institution will complete its 100 years, I believe by that time, it will be even more relevant and will be able to contribute more.

In the end, I want to say that I have been a Home Minister in all my tenures as Minister, in state and centre together, for a total of 12 years. I have met many officers after their postings. There is a system of calling on, some officers come with pleasure, some come with unwillingness and some come because of the system. But when there is a posting to BPR&D or training centre or such other place, I have not seen anyone coming happily. But I have seen, Balaji Srivastava, coming gladly and he has told me that he will look after the work of BPR&D with dedication. I believe that doing things with dedication gives results. Balaji, best wishes to you for the rest of your tenure. It is my prayer to God that under your leadership, the BPR&D may progress and continue to contribute in ensuring the internal security of the country.

Jai Hind !

47th All India Police Science Congress

28 - 29 November, 2019

Lucknow, Uttar Pradesh

Valedictory Address by

Shri Amit Shah

Hon'ble Union Home Minister,
Government of India

Please scan for speech on YouTube

Promoting Good Practices and Standards

सत्यमेव जयते

Address by the Hon'ble Home Minister, Shri Amit Shah in the valedictory function of 47th All India Police Science Congress, organised by Bureau of Police Research & Development at Lucknow on 28 - 29 November, 2019

Shri Yogi Adityanathji, famous and popular Chief Minister of Uttar Pradesh, present on the stage in today's program, Shri Keshav Prasad Mauryaji, who has been my partner in the organization for a long time, and who is now serving as the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Dr. Dinesh Sharma Ji, who has successfully nurtured the heart of Uttar Pradesh, Lucknow, and is at present serving Uttar Pradesh as the Deputy Chief Minister, Chief Secretary, Shri. R. K. Tiwari, DGP, Uttar Pradesh, OP Singh Ji, Dr. A.P. Maheshwari Ji, Shri Kaumudi Ji, on whose invitation all of us have come here and brothers and sisters from all States and Union Territories!

Today, at the valedictory function of the 47th All India Police Science Congress, after meeting you, I feel the greatest joy and pleasure. When I was the Home Minister of Gujarat, this Congress was held at Gandhi Nagar. At that time, I had the opportunity to welcome all the gentlemen and ladies who had come as delegates. Today, in this programme, I am present in front of you, as the Home Minister of the country. Many times, I think that it is more beneficial to go to the inaugural program rather than the valedictory function. What is use of ideas, when the Congress is over? What is the use of the things discussed during valediction? But I always believe that it starts only after the ceremony is over. What has been churned, it begins only after the ceremony. Therefore, one has to go to the valedictory function only.

So when I got the invitation, I decided that I will go to the function of the 47th All India Police Science Congress.

The work of the BPR&D is of coordination, exchange of best practices, finding the problems, deliberating on the solutions of the problems, finding solutions to them, and to see that they are applied down to the beat level. I believe that the only platform to share the work of BPR&D, down to the lowest level, is the All India Police Science Congress.

Since 1960, for many years, you have been organising this. I urge all of you that an All India Police Science Congress should be organised to find out and discuss all the Resolutions passed from 1960 to 2019. What happened to all the papers presented in them? If we keep on contemplating only, then what is the benefit? One Science Congress or a Special Science Congress needs to be organised to see, what happened to the issues discussed, papers presented in the Science Congress held since 1960, on how many subjects Research and Development was needed, and if Research and Development was done, what happened to the implementation part.

I believe, a deeper discussion is required on this issue. Friends, we all know that in our Constitution, internal security is also the mandate of the Home Ministry, but it is not the mandate of the Home Ministry of India, only. Our Constitution has accepted federal structure and responsibilities of law and order lie on States. But if internal security is seen in a holistic manner, it comprises many things - Border Security, Infiltration, Fake Currency, Cyber attack, smuggling of arms, and animals and human trafficking etc. It also includes narcotics trade. There are so many things that only the State police cannot deal with. This

cannot be done without coordination. The Home Ministry of India has the direct responsibility to integrate the internal and external security and coordinate with all the States by playing the role of coordinator.

Today, when we are all sitting here, I want to tell you that, while working on narcotics control, infiltration, naxalism, terrorism, even persons from the police force, who frame the policies, even they do not know that the success, which we are enjoying today, is the result of the highest sacrifice of more than 35000 Jawans. Only then the common citizen, right from our borders to the last beat, feels the sense of security.

Recently, after the arrival of Prime Minister Shri Narendra Modi at the centre, a grand Police Memorial has been constructed. I have written letters to the Chief Ministers, Home Secretaries, DGsP and Chief Secretaries. Can we make this Police Memorial a centre of police consciousness in our respective States? All of you have many important responsibilities. Our responsibility is that both the public perception of the police and the police perception of the public should change. It is very easy to cut jokes on the police. Someone will make a cartoon, someone will show a policeman with a big belly, someone will make fun in a Hindi film, but there is no service which has sacrificed more than 35,000 jawans. Can we instil this pride in every single constable? Can we use this to change the perception of 130 crore people of the country towards the police? The people of this country will have to realize that when a brother goes to his sister's house to get Rakhi tied, the police constable manages traffic. When you burst crackers with your children on Deepawali, the constable worries about law and order on that day. When you celebrate Holi with your family, then he is anxious that riots should not break out.

Our paramilitary forces guard the borders under extreme conditions, in temperatures ranging from (-) 43 to 43 degrees. I believe that the responsibility of changing the perception lies with the police officers who are sitting here. All of you sitting in high positions, it is our primary responsibility to instil this pride in the mind of every constable and to instil a sense of respect for the police in the mind of every citizen of the state. We cannot manage internal security effectively until we do this.

It is the responsibility of organizations like BPR&D also to bring this change, because, in case of any kind of incident, police is the first responder. The first confrontation is with the police and it is our prime duty to see that the public respects those who take the responsibility as the first responder.

Your delegations should meet the Chief Ministers of the States. Our Police Memorial should find a place in the tour map of all the children who come on excursion from the States. The best police performances pertaining to law & order and, the sacrifices made by the police, the major acts of saving lives of the people should be recorded. We can make documentary on such events and send it to the Police Memorial. Many visitors come to the Police Memorial and this film can be shown to them. Every week, we want to show new content in rotation, but there is insufficient material. Now, when foreign dignitaries come, we should arrange their visit to the Police Memorial. Recently, the Defence Minister of Uzbekistan had visited, the Home Minister had visited and spent one and a half hours at the Police Memorial. The President of Sri Lanka also visited the Police Memorial. It is our responsibility to enrich it, with the stories of our sacrifices, the stories of our creditable performance, and our best practices. I think, we should do it.

Friends, the scope of internal security is very large. As I said earlier, we have more than 15000 kilometers of land border, 7500 kilometers of coastline and when efforts are being made from all sides to create trouble for India, we should realise our responsibility. There are three reasons because of which there is a need to strengthen internal security in India.

First of all, there is a market of 130 crore people. In the global economy, the market of 130 crore naturally places India in the centre of the world as a powerful destination. After the arrival of Modji, the process of accelerating the economy has started. In 2004, our economy was at number 11 in the list of world economies. Now, it has moved from number 11 to number 7 within just 5 years. Our target is to make it an economy of 5 trillion dollars by 2024 and place it within the top three economies of the world. When we make these efforts, we should understand that there will be many forces trying to stop us. Then, who will face them? We will have to face them. It is our responsibility to stop cyber attacks and fake currency. It is our responsibility to improve the process of investigation, professional investigation and process of conviction in cases of cyber attack, fake currency and big scams. Only then, will we be able to realise the dream of Modiji to give momentum to our economy. So, the first reason to make our internal security effective is that, we want to become a 5 trillion dollar economy and the market of 130 crore people today remains a centre of great attraction for the whole world. If law and order and internal security is not good, it can never happen.

Secondly, as I have already said, we have land border of 15000 km and coastline of 7500 km. I do not want to comment on our neighbour. You all know, we cannot change our neighbours. But we would need

to enhance our alertness, so that, the seeds of terrorism, which are sown from there, do not get any space. In order to strengthen the security on our borders, there should be impenetrable coordination between the paramilitary forces deployed on borders and the State police, so that no one can breach it. It is our responsibility to ensure such type of coordination.

And, thirdly, our country has many religions, languages, and cultures. On the one hand, we are proud of it as the identity of our country lies in unity in diversity. But along with it, our vulnerability also increases. The enemy finds a place to create differences. Enemy finds scope to create differences amongst people through cyber attack. It is also our responsibility to prevent and eradicate such activities with an iron hand.

I believe, because of these three things, our internal security becomes very important, and also very difficult.

Friends, we have democracy and a demographic dividend with which we want to change India's destiny. And I am confident that we can change it under Modiji's leadership. But its prerequisite is that we keep the internal security in the 21st century India, strong and prepare ourselves for it. The Government of India cannot do it alone. It cannot change unless all States and Union Territories of the country are on same page and contribute towards it.

There is also a need for major change in our policing. Shri Kaumudi quoted me on this, yet, I want to say that reforms in policing are needed more than police reforms. And the direction of our reform needs to be slightly modified. This cannot be done only with technology. Nothing will happen without meeting of the minds.

I entered this big building of the UP Police; but if there is no enthusiasm in the minds of the people working in this building, this building by itself cannot give good results. Buildings cannot produce results. Only the attitudes of those working in the buildings can yield results. We have to bring in these changes.

This Science Congress should not be a mere formality but should be a harbinger of change. It should be a symbol of change, and it can happen only, when the deliberations, that take place here, are applied up to the beat level. Friends, I want to tell you that nothing can be achieved without motivational leadership. Uttar Pradesh is an example of this. Before Yogi Adityanathji became the Chief Minister of Uttar Pradesh, law & order in Uttar Pradesh was being discussed everywhere. And today, as the President of the Bharatiya Janata Party and as the Home Minister of the country, I can proudly say that Yogi Adityanath's Government has greatly improved the law & order in Uttar Pradesh, and has made it an example of good state. This is an example of motivational leadership.

Everyone who is sitting here is a leader in his own field. Who is the leader of a police force of 50 thousand to 60 thousand, on an average? It is the senior most police officer. That's why I say that this kind of meeting arranged by the BPR&D is a good platform for exchange of best practices. Let's carry the papers presented here, and the issues discussed here, to the beat level, and adopt them as per requirements of the States. Success can be achieved only when there is a unanimity between the ranks from the constables to the DGP about the approach and implementation of policing. We can achieve success only if the entire force works as a team. I believe it is badly needed.

Friends, the Government of India has taken up a huge task. It is regarding bringing about fundamental changes in the IPC and the CrPC. We will amend the Arms Act also. We are amending the Narcotics law in this session. And later on, we will also amend the IPC and the CrPC. Because, when the IPC and the CrPC were enacted, the country was under a different rule and their aim was to govern their colony. Their priority was not the citizen. Their priority was not our country. They had to perpetuate their regime. Now, we have become independent. We have our own citizens. This approach will not work. And as long as the law does not change - the IPC and the CrPC does not change - the approach will not change.

I want to give a small example. Which can be a more heinous crime than human slaughter? You have Section 302 (I.P.C.) here, but before that the sections regarding looting of treasury, rebellion against the state come. So, which is the priority? It indicates that this priority can be of the British rule, but it cannot be the priority for the sovereign and proud India. Our priority is the poorest of the poor in the country. And, if you wish to bring about changes with this spirit, I want to request you all to give your suggestions. BPR&D has sent its suggestions for changes to the Home Ministry, but I am in no hurry. Let's have wider consultations. Suggestions should come from Police Inspectors and Police Sub-Inspectors who practically use these laws on a daily basis. How do we make it simple and democratic? How to add provisions to achieve higher conviction? Bearing this in mind, a complete change should be effected. Such changes do not happen every day. These changes happen once in a century. And I believe that you have got a rare opportunity to contribute to this change in a century. Constitute a committee for this, get suggestions from all

ranks, do their screening, mould them in sections of laws and furnish your suggestions. I think all of you - in all states and regions, be they deployed in CAPFs, all experienced stakeholders, should contribute. This sacred process should change our CrPC and IPC. Later, it will be uploaded on the website. Suggestions from lawyers and judges will also be solicited and then the Government will decide. But I urge that the suggestions given by the implementers will be very useful.

The second big step that we are going to take is setting up of a National Police University. And those States which do not have a Police University should have a college, so that students who are committed to joining professional policing do not have to study too much of other subjects. They should be trained to be police specialists. After the 10th class, a student can adopt it as his/her career. Every State will have its college. There will be a central university in which all genres of policing, like forensic science, prosecution, investigation, coordination, communication, and police station management will be taught. Therefore, I appeal to you that when the Central Government sets up the University, you have to fully contribute by setting up colleges affiliated to this university wherever there is no such Police University. We will facilitate it from the Centre, but you should set up colleges in your States which could provide us specially trained police personnel and we should give priority to such candidates in the interview. Such candidates will be already trained in policing, and will only need short duration training. And if it becomes a source of employment, then I believe that all would like to get admission in this university and pass out as a good Police officer. I feel that all of you would need to motivate your States to do it.

We are planning to take yet another initiative. We are going to set up a National Forensic Science University. Our intention is to boost the conviction rate which is pitiable right now. How do we increase the conviction rate? Cases languish for years in the courts. Investigation officer is transferred somewhere else and he does not even remember the case details. Prosecution system is also not proper. But should we give up our efforts? Unless habitual offenders are punished, good people will not get the message. We will have to work out evidences to get conviction. If we want to forensically examine evidence in all cases involving punishment of more than 7 years, we need to create more Forensic Science Laboratories. Every district should have a Forensic Science Laboratory. The state should have a large forensic science laboratory and trained manpower. If we want to do this, we need youngsters trained in forensic science. Therefore, we want to create forensic science university. There is no need to spend a lot of money on it. One of its affiliated colleges should open in your State, which can be done at very little cost. You can also convert an existing science college. The senior most five Police officers should go to the Chief Minister and tell him that we want to have a college of forensic science. I think no Chief Minister will ever say no. Because, he too, wishes that eventually there should be good law & order in the State. But for this, we have to take initiative. And I think that FSL University will greatly enhance the evidence for conviction. We are also going to move forward in this direction. In this regard, your cooperation is required and, I am sure, you will cooperate.

Friends, narcotics ruins the future generations of the country. But, unfortunately, the situation is such that there is no coordination among the Central Narcotics Bureau, the State Narcotics Bureau, the

district headquarters police and the beat. The revenue department and the pharmacy people also supervise this. There is so much chaos that effective action is impossible. The Government of India is going to improve the situation. The entire structure of the Narcotics Bureau needs to be changed. We will give you a model for setting up of the Narcotics Bureau up to the beat level. We will send it in the form of an advisory, because, as per our Constitution, the Central Government can issue an advisory. But you may implement the model by changing it according to the situation in your State. The country whose youth gets addicted, can never become the leader of the world. Friends, I tell you, the time has come for India to become the leader of the world. No one can stop us. Therefore, there should be complete control over narcotics. All paramilitary forces will also help to stop it. We will also control the cultivation of the raw material. There are substances made of chemicals. We are coming up with a separate law for that. There will be a system of coordination. This law will be stricter and we are also thinking of giving trained manpower for prosecution of such cases to the states as well. We will also give good lawyers, who are proficient in it and have done specialization in the field. I have written a letter to the Deans of all the Law Universities with the request to open a separate department and to give us a list of students who are specializing in it. Nothing is impossible, if the police decides to do something. I want to tell you, let others think what they want to and let them make fun of us. Even today, when something happens in the village and a riot takes place, if two constables arrive with lathis in their hand, people say police has come and run away. Peace is restored. This is our credibility even today. It is our duty to carry it forward. I have seen many times in my public life, that only two constables come with lathis and rioters with swords run away because the law is behind you, the entire system is backing

you, justice is with you. And we should use it. The Government of India also needs your support to control narcotics. I believe, it is your responsibility to cooperate with the Government of India in this.

Secondly, unless we establish the Modus Operandi Bureau, we cannot control the law and order situation. With the registration of the FIR, its gist should come to the bureau. And after conviction, there should be psychological analysis of the criminal. It is the responsibility of the Psychology Department of the FSL to establish the Modus Operandi Bureau. What kind of system is there to catch people who are involved in particular type of stealing? What is the system to catch people who are involved in loot in a particular manner? This way, by analysing the modus operandi, we can succeed in preventing a lot of crime before it happens. If we do not analyse it at all, success cannot be achieved. So States should adopt the idea of the Modus Operandi Bureau and try to promote it.

My next request is that at the State level, there must be the system of the Director of Prosecution. Why did the case not yield results? How many adjournments do public prosecutors ask for? Why do they ask for adjournments? Unless someone fixes their accountability, there is no possibility of conviction in the cases. And that can only happen when there is an exclusive Director of Prosecution. To ensure punishment in important cases of murder, rape, big dacoity, we should analyse them at the headquarters level. Provisions and laws exist but we do not try to do it because we think there is no watch dog over us. There has to be a watch dog over those who destroy the system. We do not want the system to be destroyed. What are our representatives doing in the courts - we should have an eye on them. Should we not? I believe that we should. So my request to all of you is to take initiative and try to

institutionalize the position of the Director of Prosecution in your States. It may take two-three years or five years, but when you succeed, even after you retire, you will be satisfied that the work that I did during my tenure is rendering good service to my State. So we should do it with full dedication.

The upgradation of the Prisons Manual is very important. It is the responsibility of the Police. Making jails a separate department will achieve nothing. By and large, all this comes under the purview of law and order. It is the responsibility of the police force. So I urge all of you to form a team and work quickly for the upgradation of the Jail Manual.

Let me come to certain other points. For experimenting with new things like weapons, ballistics, traffic and transport, designing uniform and reviving the beat, having regular parade, informant system, foot march, community policing etc., we should promote and motivate junior officers. If any young SP in a district, who does this new experiment, who revives the beat system, should get some appreciation from senior officers. Someone forms the band in his district and every Saturday and Sunday, without having to march, the police band plays patriotic songs for 10 minutes, at different places in the district headquarters and that becomes the center of attraction- you may take it that the SP has done a good job, if parents stand there with their children. He deserves encouragement. Dog squads and mounted contingents - we should take care of them. All have their own role. Policing does not get stronger simply with the arrival of a vehicle, only movement become faster. I believe that whatever old wings of the police are there, they should all be reviewed at your level. Chandigarh Police has done a very good experiment regarding the beat system. This can be done even better. I urge everyone to see it once.

The Home Ministry has taken a lot of initiatives recently. The NIA Act and the UAPA have been amended. After removal of Article 370 and the Ram Janmabhoomi judgement, all of you have maintained law and order well. Even after such a big decision in Kashmir, till date, not a single person has died from police bullet. I believe that this is the biggest success of the Indian Police. We have to extend this phase of success further. We are going to do a lot of things for the system. Bill on amendment to CrPC and IPC will be brought. We are going to implement NRC. CrPC and IPC are about to undergo radical changes. Bill for FSL university will come. A bill on Raksha Shakti University will be brought. A lot of bills will be brought. I think these bills will do nothing until the leaders, who are sitting here in front of me, get motivated.

Friends, I have already said that such a two-day conference should be held especially on the research papers and decisions taken so far in the previous Congresses. First of all, you should conduct research on the problems and invite study paper on it. The suggestions which come from it, should be classified. Changes in policy should be made based on that. Their trial should be held and, after reviewing the result, it should be made permanent. Unless you follow this process, this will remain nothing except a picnic. I am sorry for my words. When you are in the district, there is always tension. Everyday Chief Minister makes calls, MLAs/MPs make calls every day. It is good that we are in Lucknow for two days. If I get a call, I will say, I am in Lucknow. Should this be our objective? Our aim is to improve the system and to achieve results. If this is what we want, then, as I said, research, research paper, changes in policy, its implementation, its review, and later its sustainability, should be our aims. If we do not do this, I think,

this conference will not be very meaningful. The vision of our Prime Minister about SMART police must have reached you. But once again I wish to tell you - S for Sensitive, M for Modern, A for Alert, R for Reliable and T for Tech-Savvy. It is our responsibility to convey the concept of SMART policing upto the constable level. India can become world leader, as imagined by Modiji, only when Law & Order is good, and this responsibility rests on all of us. I urge you to go back with realisation of this responsibility and not consider it as a burden. Best wishes to all of you!

Jai Hind !

49th FOUNDATION DAY
OF
BPR&D

28 August, 2019

New Delhi

Address by

Shri Amit Shah

Hon'ble Union Home Minister,
Government of India

Please scan for speech on YouTube

Promoting Good Practices and Standards

सत्यमेव जयते

Address by the Hon'ble Home Minister, Shri Amit Shah on the 49th Foundation Day of Bureau of Police Research & Development on 28 August, 2019

Dignitaries on the dais, Shri Kaumudi Ji, on whose invitation I am here today to attend this programme, my colleague, the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri G. Kishan Reddy Ji, Shri Ajay Bhalla Ji, who has been recently appointed as the Secretary in the Ministry of Home Affairs by the Government of India, Shri Arvind Kumar Ji, Director, I.B., Shri Deshmukh Ji, Shri Arora Ji and all the distinguished guests, brothers and sisters here in this august gathering.

Since, I am here today to celebrate the 50th anniversary of the Bureau of Police Research and Development, first of all, I extend my sincere greetings and congratulations to all the people who have contributed in ensuring the continuity and up-gradation of this institution since the very beginning.

I have long been associated with a large number of institutions and have the experience of handling a large number of institutions. When an institution, whether public or private, runs continuously for 50 years, it certainly reflects the dynamism both in work and workers. As far as the Bureau of Police Research and Development (BPR&D) is concerned, I wish it would run not only for another 50 years but also keep itself relevant for many more decades to come. This is not an easy task to remain relevant for 50 years. Many police departments run because of the constitutional obligations on the part of the government; I think it is a herculean task for BPR&D to keep itself relevant in

modernizing and upgrading the Indian police. I heartily congratulate you once again.

Mainly development-related assignments are discussed nowadays when it comes to the agenda of the government. The Department of finance discusses all sorts of various developmental works. But with the very existence of the State, law and order was the first portfolio to be established. After a considerable gap, it was followed by the Department of Justice and Social Welfare. Policing is the first thing that came into existence with the formation of a State. Our path of happiness, peace and prosperity is based on the security provided by the police. Therefore, I would like to address all the top police brass of BPR&D present here that Modi Ji wants to take this country on to the path of making it a 5 trillion-dollar economy, i.e. one amongst the 3 top economies in the world and we are sure that the country will be able to achieve his dream under his capable leadership. To make his dream come true, it is absolutely necessary to keep both internal and external security situations under tight control. We have several challenges on account of internal security in front of us. Unless we face these challenges strongly, our dream to achieve a 5 trillion dollar economy will remain unfulfilled. So, I impress upon my friends of BPR&D to rise to the occasion as the police has an important role to play in dealing with these challenges.

You are dealing with modernization, training and other tasks and playing the role of a national think tank in the matter of policing. Our country has a federal structure. On the whole, policing, Law and Order is State subject. Motivated and motivational leadership is not always there in every State. It may or may not be there in every state. In my experience good leadership can groom good policing but the graph

plummets when it is lacking. BPR&D has a responsibility to ensure that this graph never goes down, instead, it should always go up and that is possible only when we institutionalize the system. Instead of restricting the system within the boundaries of the legal framework, there should be a natural system. It should be a habit, a nature to be always in order, right from a constable to the DGP rank. When it becomes a habit to stay in order, there is little need to consult the rule books. I do not mean that rule books are meaningless or irrelevant; instead, our aim must be to achieve such an ideal condition where the rule book is not required. Gradually, the entire country should have the same concept of integrated policing from Constable to DGP. Everyone should know their role clearly and this is not possible without detailed training and this task should be executed by BPR&D as a think tank in this direction.

The legacy of the Police system goes back to Kotwali in early India. After the British rule in India, they appointed "Thanedar". The foundation of the Indian Police system was laid by them but the main idea of forming a police force at that point in time was to protect the state, not the subject or public. The concept behind policing was to stay in power. The aptitude of Police was moulded accordingly. When you refer to IPC or CrPC, you will find sections related to sedition first and the sections related to homicide later. This reflects their mentality and accordingly, the legislation was framed. Damaging railways was a more serious offence than the murder of a person. Sedition against the government was considered more serious a crime than the murder of a person. This reflects their mentality. The intent to raise the police force during British rule was to retain their power. After Independence, our first Minister of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel tried to

give it a new shape and a different concept. In the early days, Police force was used to suppress the revolution and insurrection against the British rule by the revolutionaries and safeguard their treasure. After independence, for the first time in India, the Police force was used to protect the people, their rights and human rights on the initiative launched by Sardar Patel. I am happy and satisfied that Police have done a wonderful job. We should ponder and take this task further.

My early childhood passed in village surroundings and I saw that whenever there was some conflict, the atmosphere would get violent, all the people would gather. However, two Havildars would come to the village carrying sticks in their hands and the tense atmosphere of 500 odd people would ease with a reassurance that the police have come and everything will be all right now. This is the trust Police have built over the years and this trust is required to be extended further. The world is changing fast and so are the challenges and we have to keep abreast of the changing scenario and march ahead in the direction of modernizing the Police Force.

I would like to remind you that more than 34,800 Police personnel have made the supreme sacrifice by laying down their lives in maintaining and strengthening the internal security of the country so far, and thus they were able to earn the trust of the public. Each life is important for the country and the credit goes to the entire Police force and the 34,800 police martyrs for safeguarding the internal security of the country. This needs to be appreciated and boosted.

Police reform is a long process, a continuous process and a never-ending process. We will have to keep pace with the changing scenario. Reform in Policing is a vital concept and BPR&D will have to design it

ab-initio. There is a vast difference between Police reforms and reforms in Policing. I feel reform in Policing is also required to be done. We will have to change the attitude of tackling the law and order situations. The Ministry of Home Affairs is working on this at various levels. I have some schemes in my mind and some officers are also working on this. But I think BPR&D should also think about this. The necessary amendments in the laws will be taken care of by the Government and no laxity will be done on this account. Police reform and reform in Policing are the responsibilities of BPR&D and they should ponder this from a different point of view.

Shri Kaumudi Ji came to see me a few days ago and I told him that a consultative process should be started throughout the country in order to make radical changes in CrPC and IPC. We should seek suggestions from all stakeholders and after their documentation, it should be sent to Home Ministry in a consolidated form giving your own considered views. The provisions of CrPC and IPC have not been amended for long and we have got to move ahead in this direction. Computerization in our country took place in piecemeal. Some States have implemented computerized programmes in their respective zones well before the computerized programmes of NIC were received. Even in our State Gujarat, we have implemented computerization to a considerable extent well before NIC was available. I think the computerization work which was performed in piecemeal in different places needs to be checked and I am sure that this can be done by BPR&D only. BPR&D should also work in this direction.

National Police University and Forensic Science University will be established at the national level. These institutions will be constituted in such a way that each state has an affiliated college and a

student passing 12th class who decides to join the Police force can seek admission to these colleges in any discipline. He or she can make his or her career in Police and in maintaining Internal Security. Police include different armed forces also. The training should be imparted in the right perspective and when he or she writes an exam, due weightage should be given. Such concrete arrangements should work across the country. A draft has been submitted by BPR&D in this respect which shall be kept before the cabinet within a few days and a decision will be taken on this. But BPR&D needs to act speedily and on an urgent basis to establish Forensic Science University and Forensic Science Colleges as the ratio of punishment in the cases is pitiable due to poor investigation in the country. This needs to be improved and this can be improved only with the help of scientific support of forensic science in investigation. If a challan or a charge sheet is endorsed with a scientific report of forensic science, the Judge and defence lawyer are not left with too many options. This will improve the ratio of penalizing the offenders automatically. This has to be achieved. The Government will make a forensic visit compulsory in investigation of cases. I think it will require manpower and we do not have the manpower. We will have to create manpower first. We will have to make such an arrangement that we get manpower from the Forensic Science University, the expert students of forensic science subject. We have done an experiment in Gujarat to promote Forensic Science University, which was very successful. Not even a single graduate who passed out of Gujarat Forensic Science University is unemployed. They are high in demand. I am trying to explain to you the gap between demand and supply. It is very much required. We will have to fill the gap and the more utilization of FSL we make, and amend the legal provision, the more success we will get

in punishing the criminals. Consequently, the trend to commit offences will decline. BPR&D is required to work in this direction.

I have seen that the jail manuals are being upgraded. Imparting training to staff and officers of Jail Departments is much needed in order to change their approach towards prisoners. The role of jail cannot be that of an instructor but that of an academician. Our approach should be towards making a prisoner a good citizen. Our intention should not be to punish him in order to set an example for others but to provide him with another opportunity in life. There should be radical changes in the system of Prisons in a new dimension.

I think, the modernization work you are doing under the seven columns- Weapons, Ballistics, Traffic and Transport, Building and Design, Uniform, Life Science and Electronics, there should be a proper coordination within these seven columns as they all are inter-connected. They should not be considered separate columns and a full-fledged modernization scheme should be prepared to keep this inter-relation. I have the habit of reading between the lines and I have minutely seen the modernization proposals received so far. The Budget which has been allotted should be spent in the light of a holistic approach towards modernization. Modernization Plan should include complete policing. Similarly, a modernization plan for the entire nation should be prepared for 10 years concerning complete policing. I think, only then can the modernization plan be successful in a real sense. This is absolutely necessary as Police should remain ahead of criminals and criminally minded people and should not lag behind and this can be achieved only when we adopt a holistic view of modernization.

Now, it is not the time of third-degree punishment. We will have to use scientific methods for investigation. I asked Kaumudi Ji, yesterday to think about Modus Operandi Bureau which may work at the national level and every State should have a Modus Operandi Bureau, which may take the initiative in the direction of eliminating crime by studying both modus operandi and mentality of the criminals. I think BPR&D has to work hard in this direction. Parade, Khabri network, foot patrolling, community policing all have their own importance. Modern Police does not mean that there will be an individual person to give you the information in Police Station. Telephone tapping will not serve the purpose. If you have to play the role of preventive policing, you will have to prevent the crime at the very time of commission. The practices which were being used earlier will have to be changed with time, in order to include them in the system. I know that these are vitally significant. Beat system will have to be revamped and revitalized. I feel that the old practices of policing have been used for a long time. Now the time has changed and so have the necessities. The concept should not be rejected, but should be changed to make it contemporary and time tested. BPR&D should think over all these things and should move ahead.

Forensic science should not remain limited to the Nirbhaya fund. BPR&D should ensure that budget for the Police is increased by sensitizing the Chief Ministers and Home Ministers of all States. BPR&D will have to ensure what changes are required for making an ideal Police Department in a State by conducting research and analysis, in the interest of the States. Much can be said but what has been done so far can certainly be termed satisfactory. Some good work has been done. The contribution that BPR&D has made in the area of internal

security is unparalleled, exemplary and our internal security will be strengthened with the strengthening of the Institution.

The Prime Minister has expressed a new concept of policing that is given in a video clip. I think, we all, who are associated with maintaining internal security, should create such an environment that may help in fulfilling the dream of Hon'ble Prime Minister to make it one of the top 3 economies of the world very soon. We should ensure policing in the country in such a way that we face the challenges of internal security with a firm hand. The role of the think tank which you are playing also need to be strengthened. BPR&D should play a proactive role and should expand its purview.

I congratulate the officers and staff of various ranks coming from different States, specially from small States of the North-East, who have been awarded medals today on the occasion of the 50th anniversary of BPR&D. I extend my congratulations and best wishes for a very bright role and history of BPR&D and hope that the Home Minister of the country would come to celebrate the centenary of this Institution.

Jai Hind !

माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और मंच पर आसीन गणमान्य अतिथियों द्वारा ब्यूरो के प्रकाशनों का विमोचन

ब्यूरो के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव का स्वागत संबोधन

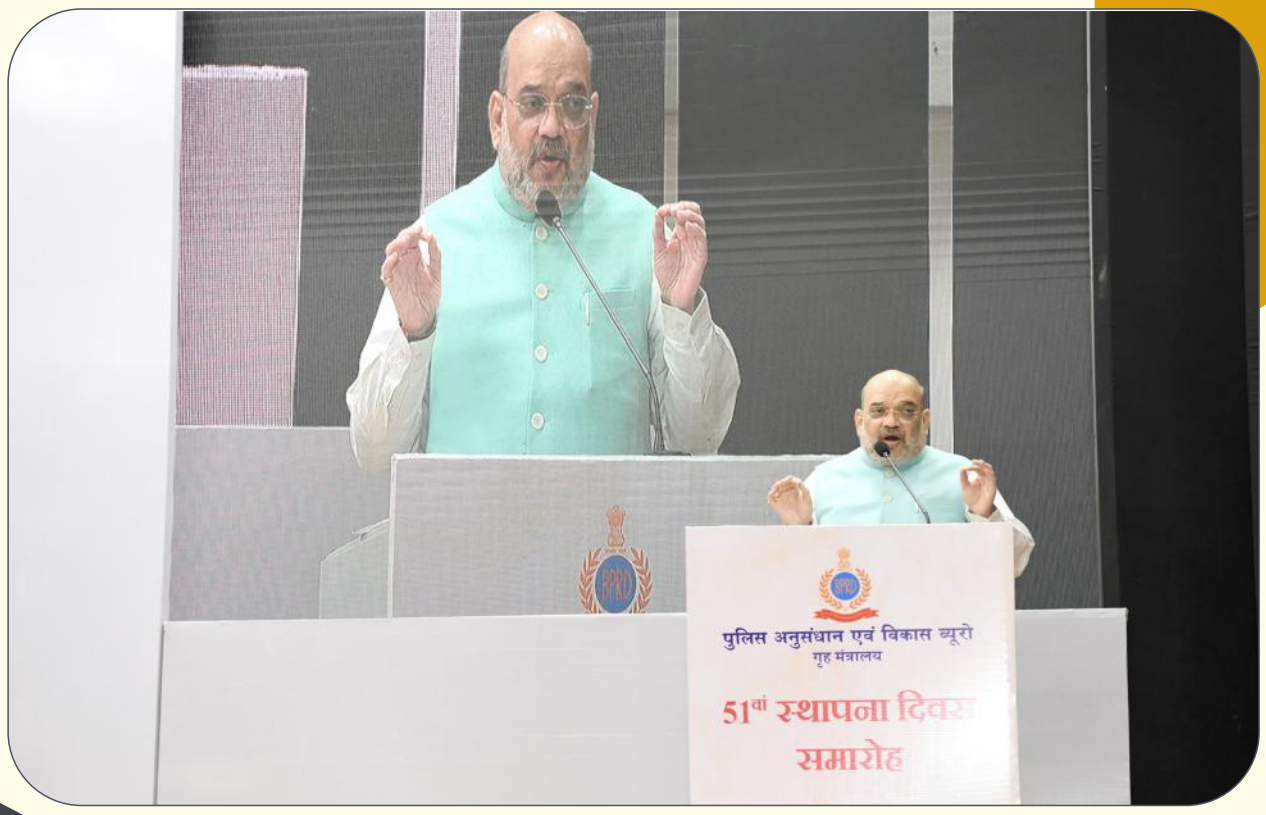

मुख्य अतिथि माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन

मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए ब्यूरो के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव